

MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani
Advocate Bombay High Court.

Specialist in Multi Media Law and Regulation/
Corporate Law and Regulation and Taxation.



मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं
पर एक सामयिक स्तंभ

लेखक: अशोक मनसुखानी

एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट

मल्टी मीडिया कानून और रेग्यूलेशन/कॉर्पोरेट कानून और रेग्यूलेशन
और टैक्सेशन के विशेषज्ञ।

CHURN IN MEDIA IS GOOD NEWS

A. WHO WILL ULTIMATELY WIN IN THE ZEE-SONY MERGER?

A.1. THE MERGER ANNOUNCEMENT ON SEPTEMBER 22, 2021

On September 22, 2021, Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) informed the Stock Exchanges of having entered into a non-binding term sheet to bring together their linear networks, digital assets, production operations and program libraries with Sony Pictures Network India Ltd. (SPNI).

The Stock Exchange Release by Zee Entertainment stated:

- ◆ The Board of Directors of Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) (present and voting) in its Board Meeting held on 21st September 2021 unanimously provided an in-principal approval for the merger between Sony Pictures Networks India (SPNI) & ZEEL.
- ◆ The Board has evaluated not only on financial parameters but also on the strategic value which the partner brings to the table. The Board concluded that the merger would be in the best interest of all the shareholders & stakeholders.
- ◆ The merger is in line with ZEEL's strategy of achieving higher growth and profitability as a leading Media & Entertainment Company across South Asia. The Board has authorised the Management of ZEEL to activate the required due diligence process.



मीडिया में मंथन अच्छी खबर है

ए. जी-सोनी विलय में अंततः कौन जीतेगा?

ए.1. 22 सितंबर 2021 को विलय की घोषणा

22 सितंबर 2021 को जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जेडईईएल) ने स्टॉक एक्सचेंजों को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड (एसपीएनआई) के साथ अपने टेरस्ट्रियल नेटवर्क, डिजिटल संपत्ति, उत्पादन संचालन और प्रोग्राम लाइब्रेरी को एक साथ लाने के लिए एक गैर बाध्यकारी टर्म शीट में प्रवेश की सूचना दी।

जी इंटरटेनमेंट द्वारा स्टॉक

एक्सचेंज को यह बात एक विज्ञापित के द्वारा बतायी गयी।

◆ जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) (वर्तमान और मतदान) द्वारा 21 सितंबर 2021 को हुई अपनी बोर्ड की बैठक में स्टॉक एक्सचेंज रिलीज ने सर्व सम्मति से सोनी पिक्चर्स ऑर्कस इंडिया (एसपीएनआई) और

जेडईईएल के बीच विलय के लिए सर्वसम्मति से सैद्धांतिक मंजूरी दी।

- ◆ बोर्ड ने न केवल वित्तीय मानकों पर बल्कि उस रणनीतिक मूल्य पर भी मूल्यांकन किया है जो कि साझेदार अपने साथ लायेंगे। बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि विलय सभी शोयारधारकों के सर्वोत्तम हित में होगा।
- ◆ विलय दक्षिण एशिया में एक प्रमुख मीडिया और मनोरंजन कंपनी के रूप में उच्च विकास और लाभप्रदता प्राप्त करने की जी की रणनीति के अनुरूप है। बोर्ड ने आवश्यक ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए जेडईईएल के प्रबंधन को अधिकृत किया है।



- ◆ The shareholders of SPNI will hold a majority stake in the merged entity. The shareholders of SPNI will also infuse growth capital into SPNI as part of the merger. SPNI has approximately USD 1.575 billion at closing for use in pursuing other growth opportunities.
- ◆ Basis the existing estimated equity values of ZEEL and SPNI, the indicative merger ratio would have been 61.25% in favour of ZEEL. However, with the proposed infusion of growth capital into SPNI, the resultant *merger ratio* is expected to result in 47.07% of the merged entity being held by ZEEL shareholders and the balance 52.93% of the merged entity be held by SPNI shareholders.
- ◆ ZEEL & SPNI have entered into a *non-binding term sheet* to combine both companies' linear networks, digital assets, production operations and program libraries.
- ◆ The *term sheet* provides an exclusive period of 90 days. ZEEL and SPNI will conduct mutual diligence and finalise definitive agreement(s). The *merged entity* will be a publicly listed company in India.
- ◆ As part of the transaction, Mr Punit Goenka will continue to be the Managing Director and CEO of the merged entity.
- ◆ Further, specific non-compete arrangements will be agreed upon between the promoters of ZEEL and the promoters of SPNI.
- ◆ According to the term sheet, the Promoter Family is free to increase its shareholding from the current ~4% to up to 20% in a manner that is in accordance with applicable law.
- ◆ The majority of the Board of Directors of the merged entity will be nominated by Sony Group.
- ◆ It is anticipated that the final transaction would be subject to the completion of customary due diligence and execution of definitive agreements and required corporate, regulatory, and third-party approvals, including the votes of ZEEL's shareholders.
- ◆ ZEEL's strong expertise in content creation and its deep consumer connect established over the last 3 decades, coupled with SPNI's success across entertainment genres (including gaming and sports), will add significant value to the merged entity and its management team, thereby increasing shareholder value multi-fold.
- ◆ विलय की गयी इकाई में एसपीएनआई के शेयरधारक बहुलांश हिस्सेदारी रखेंगे। एसपीएनआई के शेयरधारक विलय के हिस्से के रूप में एसपीएनआई में विकास पूंजी भी डालेंगे। अन्य विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने में उपयोग के लिए एसपीएनआई के पास लगभग 1.575 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ◆ जेडईईएल और एसपीएनआई के मौजूदा अनुमानित इक्विटी मूल्यों के आधार पर जेडईईएल के पक्ष में सांकेतिक विलय का अनुपात 61.25% होता है। हालांकि एसपीएनआई में विकास पूंजी के प्रस्तावित निवेश के साथ, परिणामी विलय अनुपात के परिणामस्वरूप विलय की गयी इकाई का 47.07% हिस्सा जेडईईएल शेयरधारकों के पास होगा और शेष 52.93% विलय वाली इकाई एसपीएनआई शेयरधारकों के पास होगी।
- ◆ जेडईईएल व एसपीएनआई ने दोनों कंपनियों के टेरस्ट्रियल टेलीविजन, डिजिटल संपत्ति, उत्पादन संचालन और प्रोग्राम लाइब्रेरी को संयोजित करने के लिए एक गैर बाध्यकारी टर्म शीट में प्रवेश किया है।
- ◆ टर्म शीट 90 दिनों की एक विशेष अवधि प्रदान करती है। जेडईईएल और एसपीएनआई आपसी परिश्रम करेंगे और निश्चित समझौते को अंतिम रूप देंगे। विलय की गयी इकाई भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी होगी।
- ◆ लेनदेन के हिस्से के रूप में श्री पुनीत गोयनका विलय की गयी इकाई के प्रबंध निदेशक और सीईओ बने रहेंगे।
- ◆ इसके अलावा जेडईईएल के प्रमोटरों और एसपीएनआई के प्रमोटरों के बीच विशिष्ट गैर प्रतिस्पर्धा व्यवस्था पर सहमति होगी।
- ◆ टर्म शीट के अनुसार प्रमोटर परिवार अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा 4% से 20% तक बढ़ाने को स्वतंत्र है, जो कि लागू कानून के अनुसार है।
- ◆ विलय की गयी इकाई के अधिकांश निदेशक मंडल सोनी समूह द्वारा नामित किये जायेंगे।
- ◆ यह अनुमान है कि अंतिम लेनदेन प्रथागत उचित परिश्रम के पूरा होने और निश्चित समझौते के निष्पादन और आवश्यक कॉर्पोरेट, नियामक और तीसरे पक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें जेडईईएल के शेयरधारकों के वोट शामिल हैं।
- ◆ कंटेंट निर्माण में जेडईईएल की मजबूत विशेषज्ञता और पिछले 3 दशकों में स्थापित इसका गहरा उपभोक्ता संपर्क, मनोरंजन शैलियों (गेमिंग और स्पोर्ट्स सहित) में एसपीएनआई की सफलता के साथ विलय की गयी इकाई और इसकी प्रबंधन टीम के लिए महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ देगा, जिससे शेयरधारक मूल्य कई गुना बढ़ जायेगा।

Simultaneously **Sony Pictures Network India** also issued a media release on its website on **September 22, 2021** stating:

- ◆ Today, **Sony Pictures Networks India (SPNI)** and **Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL)** announced that they have entered into an exclusive, non-binding **Term Sheet** to combine both companies' linear networks, digital assets, production operations, and program libraries.
- ◆ The **non-binding Term Sheet** provides an **exclusive negotiation** period of **90 days**. **ZEEL** and **SPNI** will conduct mutual diligence and negotiate definitive, binding agreements.
- ◆ The combined company would be publicly listed in India and better positioned to lead the consumer from traditional pay T.V. into the digital future.
- ◆ The merger of **ZEEL** and **SPNI** would bring together two leading Indian media network businesses, benefitting consumers throughout India across content genres, from film to sports. The combined company is expected to benefit all stakeholders, given strong synergies between **ZEEL** and **SPNI**.
- ◆ Under the terms of the non-binding **Term Sheet**, **Sony Pictures Entertainment**, the parent company of **SPNI**, would invest growth capital so that **SPNI** has a cash balance of approximately **USD 1.575 billion** at closing for use to enhance the combined company's digital platforms across technology and content, ability to bid for broadcasting rights in the fast-growing sports landscape and pursue other growth opportunities.
- ◆ **Sony Pictures Entertainment** would hold a majority stake in the combined company.
- ◆ Currently, **ZEEL** Managing Director & CEO Mr Punit Goenka is to lead the combined company.
- ◆ The combined Company's Board of Directors would include Directors nominated by **Sony Group** and result in **Sony Group** having the right to nominate the majority of the Board members.
- ◆ It is anticipated that a final transaction would be subject to completion of customary due diligence, negotiation, and execution of definitive binding agreements and required corporate, regulatory, and third-party approvals, including **ZEEL** shareholder vote.

इसके साथ ही **सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया** ने भी **22 सितंबर 2021** को अपनी वेबसाइट पर एक **मीडिया विज्ञप्ति** जारी की जिसमें कहा गया है:

- ◆ आज, **सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई)** और **जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल)** ने घोषणा की कि उन्होंने दोनों कंपनियों के **टेरस्ट्रियल नेटवर्क, डिजिटल संपत्तियों, उत्पादन संचालन और कार्यक्रम लाइब्रेरी** को संयोजित करने के लिए एक विशेष, गैर-बाध्यकारी **टर्म शीट** में प्रवेश किया है।
- ◆ गैर बाध्यकारी **टर्मशीट 90 दिनों** की विशेष बातचीत की अवधि प्रदान करती है। **जेडईईएल** व **एसपीएनआई** परस्पर परिश्रम करेंगे और निश्चित, बाध्यकारी समझौतों पर बातचीत करेंगे।
- ◆ संयुक्त कंपनी को भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जायेगा और उपभोक्ता को पारंपरिक पे टीवी से डिजिटल भविष्य में ले जाने के लिए बेहतर स्थिति में रखा जायेगा।
- ◆ **जेडईईएल** और **एसपीएनआई** का विलय दो प्रमुख भारतीय मीडिया नेटवर्क व्यवसायों को एक साथ लायेगा, जिससे पूरे भारत में उपभोक्ताओं को फिल्मों से लेकर खेल तक सभी कार्यक्रम शैलियों का लाभ होगा। **जेडईईएल** व **एसपीएनआई** के बीच मजबूत तालमेल को देखते हुए संयुक्त कंपनी से सभी हितधारकों को लाभ होने की उम्मीद है।
- ◆ गैर बाध्यकारी **टर्मशीट** की शर्तों के तहत **एसपीएनआई** की मूल कंपनी **सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट** कंपनी में विकास पूंजी लगायेगी। ताकि **एसपीएनआई** के पास लगभग **1.575 बिलियन अमेरिकी डॉलर** नकद शेष हो, जिसका उपयोग तकनीकी के क्षेत्र में संयुक्त कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए किया जा सके। जिससे कंपनी के पास सामग्री, तेजी से बढ़ते खेल परिदृश्य में प्रसारण अधिकारों के लिए बोली लगाने और विकास के अन्य अवसरों का पीछा करने की क्षमता होगी।
- ◆ **सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट** की संयुक्त कंपनी में बहुसंख्यक हिस्सेदारी होगी।
- ◆ वर्तमान में **जेडईईएल** के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री पुनीत गोयनका संयुक्त कंपनी का नेतृत्व करेंगे।
- ◆ संयुक्त कंपनी के निदेशक मंडल में **सोनी समूह** द्वारा नामित निदेशक शामिल होंगे और इसके परिणामस्वरूप **सोनी समूह** को बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा।
- ◆ यह अनुमान है कि अंतिम लेन देन प्रथागत उचित परिश्रम, बातचीत और निश्चित बाध्यकारी समझौते के निष्पादन और **जेडईईएल** शेयरधारक वोट सहित आवश्यक कॉर्पोरेट, नियामक और तीसरे पक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

COMMENT

The announcement came after months of negotiation between the two major media groups and is intended to help both companies. Reuters estimates that when the merger goes through, it will consist of “75 news, entertainment, sports, and movie channels in more than 10 languages, stands to become India's biggest player, with a market share of 27% outstripping that of Disney's Star India, at 24%. Sony will infuse growth capital of nearly \$1.6 billion into an Indian holding company taking a majority stake in Zee Enterprises. The Sony funds will be used to enhance the combined company's digital platforms and its ability to bid for broadcasting rights in the fast-growing sports landscape, the two firms have said.”

The announcements, while broadly similar, do have two different points of emphasis. These have largely gone unnoticed in the largely laudatory media coverage which has fawned over the new deal.

The first is while the ZEEL Press Release definitively states that “As part of the transaction, Mr Punit Goenka will continue to be the Managing Director and CEO of the merged entity. But the SPNI media release has a different spin of emphasis it says “currently ZEEL Managing Director & CEO Mr Punit Goenka is to lead the combined company.” This is contrary to media plugs that the Term Sheet (not so far available in the public sphere) that Mr Punit Goenka will continue as CEO/MD for five years.

The second is while the Zee media release on the infusion of funds by SPNI very generally states that “the shareholders of SPNI will also infuse growth capital into SPNI as part of the merger such that SPNI has approximately USD 1.575 billion at closing, for use in pursuing other growth opportunities.” The SPNI Media release is more specific as it states that “Sony Pictures Entertainment, the parent company of SPNI, would invest growth capital so that SPNI has a cash balance of approximately USD 1.575 billion at closing for use to enhance the combined company's digital platforms across technology and content, ability to bid for broadcasting rights in the fast-growing sports landscape and pursue other growth opportunities.”

How this emphasis of difference will pan out remains to be seen.

टिप्पणी

घोषणा दो प्रमुख मीडिया समूहों के बीच महीनों की बातचीत के बाद हुई और इसका उद्देश्य दोनों कंपनियों की मदद करना है। रॉयटर्स का अनुमान है कि जब विलय हो जायेगा तो इसमें 75 मनोरंजन, समाचार, खेल, और 10 से अधिक भाषाओं में शामिल होंगे, जो भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए खड़ा है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी डिज्नी के स्टार इंडिया के 24% के मुकाबले 27% है। सोनी, जी एंटरप्राइजेज में बहुमत हिस्सेदारी लेने वाली भारतीय होल्डिंग कंपनी में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की विकास पूंजी डालेगी। सोनी फंड का उपयोग संयुक्त कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और तेजी से बढ़ते खेल परिदृश्य में प्रसारण अधिकारों के लिए बोली लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जायेगा। यह बात दोनों कंपनियों ने बतायी।

घोषणायें मोटे तौर पर समान हैं, पर जोर देने के दो अलग अलग बिंदु हैं। बड़े पैमाने पर प्रशंसनीय मीडिया कवरेज में इन पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसने नये सौदे पर पानी फेर दिया। पहला यह है कि जेडईईएल प्रेस विज्ञापित में निश्चित रूप से कहा गया है कि लेन देन के हिस्से के रूप में श्री पुनीत गोयनका विलय की गयी इकाई के प्रबंध निदेशक और सीईओ बने रहेंगे। लेकिन एसपीएनआई मीडिया रिलीज में एक अलग तरह का जोर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में जेडईईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री पुनीत गोयनका संयुक्त कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह मीडिया प्लग के विपरित है कि टर्म शीट (सार्वजनिक क्षेत्र में अब तक उपलब्ध नहीं है) कि श्री पुनीत गोयनका सीईओ/एमडी के रूप में पांच साल तक बने रहेंगे।

दूसरा यह कि जी मीडिया एसपीएनआई द्वारा अधिक धन के इन्व्यूजन पर जारी करता है जिसमें आमतौर पर कहा गया है कि ‘एसपीएनआई के शेयरधारक विलय के हिस्से के रूप में एसपीएनआई के विकास पूंजी भी डालेंगे जैसे, कि एसपीएनआई के पास अन्य विकास अवसरों का पीछा करने के लिए लगभग 1.575 बिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग करेगा। एसपीएनआई मीडिया रिलीज अधिक विशिष्ट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ‘सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, एसपीएनआई की मूल कंपनी, विकास पूंजी का निवेश करेगी, ताकि एसपीएनआई के पास संयुक्त कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए बंद होने पर लगभग 1.575 बिलियन अमेरिकी डालर का नकद शेष हो। तकनीकी और कार्यक्रम, तेजी से बढ़ते खेल परिदृश्य में प्रसारण अधिकारों के लिए बोली लगाने की क्षमता और विकास के अन्य अवसरों का पीछा करने की क्षमता है।’

विभिन्नता का यह जोर कैसे खत्म होगा, यह देखा जाना बाकी है।

A.2 THE INVESCO IMBROGLIO

1. As per its latest presentation for **2021**, Invesco claims to be a leading global investment firm with **US\$1.5 trillion** global assets under Management. It has specialised investment teams managing investments across a wide range of asset classes and investment styles with more than **8,200** employees worldwide and an on-the-ground presence in more than **20** countries, serving clients in more than **120** countries. It offers strategic assistance in various spheres, including achieving strong investment performance. It desires to be instrumental to our client's success. It aims to harness the power of its global platform. It wishes to perpetuate a high-performance organisation. It wants to deliver an investment experience that helps people get more out of life. It wants to put its clients at the centre of all it does. It has a pure focus on investments.
2. **Invesco** has been a long-time investor in **Zee**. In **2019** it came in as a white knight to help the **Zee Promoters** by infusing more funds raising its stakes to **18.8%**. On **1 August 2019**, **Essel Group** (Promoter of **ZEEL**) announced that **Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund**, a long-time investor in **Zee Entertainment Enterprises (ZEE)**, has agreed to acquire an **11%** stake in the Company for **Rs 4,224 crore** at **Rs 400** per share. This investment set **ZEE's** enterprise value at **Rs 37,439 crore (\$5.44 billion)**.
3. The primary purpose of the sale of **11%** additional stake in **ZEEL** was due to the deadline set by various mutual funds, which had an exposure of roughly **Rs 5,200 crore** to the **Essel Group's** overall debt, had set a deadline of **July 31, 2019** to receive their dues before selling the shares in the market. The **M.D.** **Mr Punit Goenka** stated that **Invesco Oppenheimer** has come in as a pure equity investor without any Board Seat or special conditions. Significantly enough, **Oppenheimer** had no right of first refusal on any further stake sale by **ZEE** to any other, nor did it do any due diligence. The existing Management would continue. **Oppenheimer's** holding was planned to increase to **18.8%** after the closure of the deal.
4. In just two years, **Invesco Oppenheimer**, on **September 15, 2021**, demanded that the Board of **ZEEL** be reconstituted and specifically asked for the

ए.2 इन्वेस्को गुथी

1. **2021** के लिए अपनी नयी प्रस्तुति के अनुसार **इन्वेस्को** ने प्रबंधन के तहत **1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर** की वैश्विक संपत्ति के साथ एक प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म होने का दावा किया है। इसमें दुनियाभर में **8200** से अधिक कर्मचारियों के साथ परिसंपत्ति वर्गों और निवेश शैलियों की एक विस्तृत शृंखला में निवेश का प्रबंधन करने वाली विशेष निवेश टीम हैं और **20** से अधिक देशों में इसकी जमीनी उपस्थिति है, जिसकी सहायता से यह **120** से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें मजबूत निवेश प्रदर्शन प्राप्त करना शामिल है। यह हमारे ग्राहक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य अपने वैश्विक प्लेटफॉर्म की शक्ति को दोहन करना है। यह एक उच्च प्रदर्शन वाले संगठन को कायम रखना चाहता है। यह एक निवेश अनुभव प्रदान करना चाहता है जो लोगों को जीवन से अधिक लाभ उठाने में मदद करता है। यह अपने ग्राहकों को अपने सभी कार्यों के केंद्र में रखना चाहता है। इसका शुद्ध फोकस निवेश पर है।
2. **इन्वेस्को** लंबे समय से **जी** में निवेशक रहा है। **2019** में यह **जी के प्रमोटरों** की मदद करने के लिए मसीहा के रूप में सामने आया, जिसने आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी **18.8%** प्रतिशत कर दी। **1 अगस्त 2019 को एसेल ग्रुप (जेडईईएल के पूर्वतक)** ने घोषणा की कि **जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जी)** में लंबे समय तक निवेशक कंपनी **इन्वेस्को ओपेनहाइमर मार्केट फंड** ने कंपनी में **4224** करोड़ रुपये में **400** रुपये प्रति शेयर की दर से **11%** हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हो गया है। इस निवेश ने **जी** का उद्यम मूल्य **37,439 करोड़ रुपये (5.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर)** निर्धारित किया।
3. **जेडईईएल** में **11%** अतिरिक्त हिस्सेदारी की विक्री का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न म्यूचुअल फंडों द्वारा निर्धारित समय सीमा के कारण था, जिसका एसेल समूह के कुल ऋण में लगभग **5200 करोड़ रुपये** का जोखिम था, ने बाजार में शेयर बेचने से पहले अपना बकाया प्राप्त करने के लिए **31 जुलाई 2019** की समय सीमा निर्धारित की थी। एमडी श्री पुनीत गोयनका ने कहा कि **इन्वेस्को ओपेनहाइमर** बिना किसी बोर्ड सीट या विशेष शर्तों के एक शुद्ध इक्विटी निवेशक के रूप में आया है। महत्वपूर्ण रूप से **ओपेनहाइमर** के पास **जी** द्वारा किसी अन्य को किसी और हिस्सेदारी की विक्री पर पहले इंकार करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही इसने उचित परिश्रम किया। मौजूदा प्रबंधन जारी रहेगा। सौदा के पूरा होने के बाद **ओपेनहाइमर** की हिस्सेदारी बढ़कर **18.8%** प्रतिशत होने की उम्मीद है।
4. केवल दो वर्षों में **इन्वेस्को ओपेनहाइमर** ने **15 सितंबर 2021** को **जेडईईएल** के बोर्ड को पुनर्गठित करने की मांग की

dropping of two non-independent non-executive Directors. **Mr Manish Chokhani** and **Mr Ashok Kurian**, and **Mr Punit Goenka**. The letter also proposed the appointment of **six independent directors** at the forthcoming Extra ordinary General Body Meeting (EGM), including Mr Surendra Singh Sirohi, Mr Naina Krishna Murthy, Mr Rohan Dhamija, Ms Aruna Sharma, Mr Srinivasa Rao Addepalli and Mr Gaurav Mehta.

5. Almost simultaneously, **ZEEL** announced on **13 September 2021** that the two long time non-independent non-executive Directors, **Mr Manish Chokhani** and **Mr Ashok Kurian**, had resigned. However, Mr Chokhani and Mr Kurian have submitted their resignations before the extraordinary general meeting (EGM). In a stock exchange filing, Zee said the two had resigned as Non-Executive non-independent directors. Mr Chokhani, the company said, has resigned due to "changed life circumstances and perspectives post covid". At the same time, the reason cited for Mr Kurian was his "preoccupation." Both tenures ended as of 13 September 2021. Mr Punit Goenka continued as CEO and M.D.
6. At the **Annual General Body** meeting held on **September 14, 2021**, there were six topics on the agenda, including passage of audited accounts on **March 31, 2021**; confirmation of dividend paid on preference shares for the year ending **31 March 2021**; declaration of annual dividend; ratification of cost auditor remuneration for **F.Y. 2020-21**; appointment of Mr Sasha Mirchandani as Independent Director; and appointment of Mr Vivek Mehta as Independent Director. It is noteworthy that the Invesco demands for change of Mr Punit Goenka as Director and appointment as six Independent Directors did not come up for discussion.
7. A week later, Zee and Sony announced the merger on **September 22, 2021**. **Invesco** reiterated its demand to reconstitute the Board of Directors and stuck to its demand for Mr **Punit Goenka** to step down from the Board of Directors. In a letter dated **23.09.2021**, **Invesco** made the following hard-hitting points:
 - ❖ **We continue to believe that the business is valuable, whether on its own or in strategic alignment with partners such as Sony.**

और विशेष रूप से दो गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने के लिए कहा। ये हैं **श्री मनीष चोखानी, श्री अशोक कुरियन** और **श्री पुनीत गोयनका**। पत्र में श्री सुरेंद्र सिंह सिर्रोही, श्री नैना कृष्णमूर्ति, श्री रोहन धमीजा, सुश्री अरुणा शर्मा, श्रीनिवास राव अडेपल्ली, और श्री गौरव मेहता सहित आगामी असाधारण आम सभा (**ईजीएम**) में **छह स्वतंत्र निदेशकों** को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

5. लगभग इसी समय **जेडईईएल** ने **13 सितंबर 2021** को घोषणा की कि दो लंबे समय तक गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक **श्री मनीष चोखानी** और **श्री अशोक कुरियन** ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि श्री चोखानी और श्री कुरियन ने असाधारण जनरल मीटिंग (ईजीएम) के दौरान अपना इस्तीफा सौंप दिया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी सूचना में जी ने कहा कि दोनों ने गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। श्री चोखानी, कंपनी ने कहा कि 'कोविड के बाद जीवन की परिस्थितियों और दृष्टिकोण में बदलाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। साथ ही **श्री कुरियन** के लिए उनकी व्यस्तता के कारण का हवाला दिया गया। दोनों के कार्यकाल **13 सितंबर 2021** को समाप्त हो गये। **श्री पुनीत गोयनका सीईओ और एमडी** के रूप में काम करना जारी रखेंगे।
6. **14 सितंबर 2021** को आयोजित **वार्षिक आम सभा** की बैठक में एजेंडे में छह विषय थे, जिनमें **31 मार्च 2021** को लेखापरीक्षित खातों को पारित करना शामिल था, **31 मार्च 2021** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिमानी शेयरों पर भुगतान किये गये लाभांश की पुष्टि, वार्षिक लाभांश की घोषणा, **वित्तीय वर्ष 2020-21** के लिए लागत लेखा परीक्षक पारिश्रमिक का अनुसमर्थन, श्री साशा मीरचंदानी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति, और श्री विवेक मेहता की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। उल्लेखनीय है कि **इन्वेस्को** ने पुनीत गोयनका को निदेशक के रूप में बदलने और छह अन्य स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति की मांग पर चर्चा नहीं की।
7. एक सप्ताह बाद **जी** और **सोनी** ने **22 सितंबर 2021** को विलय की घोषणा की। **इन्वेस्को** ने निदेशक मंडल के पुनर्गठन की अपनी मांग दुहराई और **श्री पुनीत गोयनका** के निदेशक मंडल से पद छोड़ने की मांग से अड़े रहे। **23.09.2021** के एक पत्र में **इन्वेस्को** ने निम्नलिखित कठिन बिंदुओं का उल्लेख किया:
 - ❖ **हमारा मानना है कि व्यवसाय मूल्यवान है, चाहे वह अपने दम पर या सोनी जैसे भागीदारों के साथ रणनीतिक भागीदारी में हो।**

- ❖ Decisions of *strategic material import* must follow and not precede actions towards establishing a proper and independent governance structure as determined by the company's shareholders.
- ❖ In this context, and against the backdrop of our EGM requisition, your disclosure of **22 September 2021** is symptomatic of the erratic manner in which important and serious decisions are handled at the company.
- ❖ **Precisely to protect shareholder value and in the exercise of our statutory rights as an ordinary shareholder, we have called upon the company to hold an EGM, and it is your duty under company law to do so. At this EGM, shareholders of the company will decide the composition of the Company's Board of Directors in a free and democratic manner.**
- ❖ Towards this end, Invesco has proposed the *removal* of non-independent directors and recommended additional independent directors coming from diverse backgrounds and are expected to bring additional professionalism, guidance, and standards of governance to the operations of the company. Together with the existing set of I.D.s, we believe that the Company's Board will have the depth to navigate the company into the future.
- ❖ We continue to have *immense faith* in the commitment and passion of the company's employees and believe the bench of talent is deep within the Company and India's vibrant media industry.
- ❖ **Our actions are intended to create a healthy long-term future for the company. Strengthened governance is a necessary first step.**
- ❖ An Invesco spokesperson Jeanee Terrio told **Business Today** over email that it sent **Zee** an EGM requisition letter on **11 September 2021**, exercising its rights as ordinary shareholders to *protect shareholder value* in the company. "This initiative, which is unique in the history of our fund, was taken with the belief that a newly constituted Board elected by its shareholders would be foundational in reviving the long-term health of the business.
- ❖ On **23 September 2021**, we reiterated our call for an EGM in a letter to the Board of Directors of **Zee**," the mail said.
- ❖ **रणनीतिक सामग्री आयात** के निर्णयों का पालन किया जाना चाहिए और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा निर्धारित उचित और स्वतंत्र शासन संरचना की स्थापना की दिशा में कार्रवाई से पहले नहीं होनी चाहिए।
- ❖ इस संदर्भ में और हमारी **ईजीएम** मांग की पृष्ठभूमि में **22 सितंबर 2021** का आपका प्रकटीकरण, कंपनी में महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णयों को संभालने के अनिश्चित तरीके का लक्षण है।
- ❖ **सटीक रूप से शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करने के लिए और एक सामान्य शेयरधारक के रूप में हमारे वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हमने कंपनी से एक ईजीएम आयोजित करने का आग्रह किया है, और ऐसा करना कंपनी कानून के तहत आपका कर्तव्य है। इस ईजीएम में कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से तय करेंगे।**
- ❖ इस दिशा में, इन्वेस्को ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों को हटाने का प्रस्ताव दिया है और विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की की सिफारिश की है और इनसे कंपनी के संचालन में अतिरिक्त व्यवसायिकता, मार्गदर्शन और शासन के मानकों के लाने की उम्मीद है। आईडी के मौजूदा सेट के साथ हम मानते हैं कि कंपनी के बोर्ड के पास भविष्य में कंपनी को नेविगेट करने की गहराई होगी।
- ❖ हमें कंपनी के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और जुनून में **अत्यधिक विश्वास** है और हमारा मानना है कि प्रतिभा की धनी कंपनी और भारत के जीवंत मीडिया उद्योग के भीतर बहुत गहरी पहुंच है।
- ❖ **हमारे कार्यों का उद्देश्य कंपनी के लिए एक स्वस्थ दीर्घकालिक भविष्य बनाना है जिसके लिए मजबूत शासन एक आवश्यक पहला कदम है।**
- ❖ इन्वेस्को के प्रवक्ता जीनीन टेरियो ने ईमेल पर **बिजनेस टूडे** को बताया कि उसने कंपनी में **शेयरधारक मूल्य की रक्षा** के लिए सामान्य शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए **जी** को **11 सितंबर 2021** को एक ईजीएम मांग पत्र भेजा था। **यह पहल जो हमारे फंड के इतिहास में अद्वितीय है, इस विश्वास के साथ की गयी थी कि इसके शेयरधारकों द्वारा चुने गये एक नवगठित बोर्ड व्यवसाय के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में आधारभूत होगा।**
- ❖ मेल बताता है कि **23 सितंबर 2021** को हमने **जी** के निदेशक मंडल को लिखे एक पत्र में ईजीएम के लिए आहवान को दोहराया।

❖ *It goes on to say that "the company's failure to take steps within its notice period (21 days according to law) to call an EGM, coupled with its delay in noticing our EGM (request) on 11 September 2021 and failure to notice our September letter to the exchanges, has prompted us to file a petition before the NCLT to enforce our rights as shareholders to call for this EGM of the company".*

8. On **29.09.2021**, Invesco fired the first missile by filing a petition against Zee in the National Company Law Tribunal Mumbai. The Petition was filed under **Section 98** and **100** of the **Companies Act 2013**. **Section 98** empowers the NCLT to order the convening of an **Extra ordinary General Body** meeting, and **Section 100** gives a shareholder with not less than **one-tenth** of paid-up share capital the power to request an EGM.

9. **Section 98** reads as under

If for any reason it is impracticable to call a meeting of a company, other than an annual general meeting, in any manner in which meetings of the company may be called, or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this Act or the articles of the company, the Tribunal may, either suo motu or on the application of any director or member of the company who would be entitled to vote at the meeting.

10. **Section 100** reads as under:

- 1) The Board may, whenever it deems fit, call an **extraordinary general meeting** of the company.
- 2) The Board shall, at the **requisition** made by, —
 - (a) in the case of a company having a share capital, such number of members who hold, on the date of the receipt of the requisition, not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the company as on that date carries the right of voting.
- 3) The **requisition** made under sub-section (2) shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionists and sent to the registered office of the company.
- 4) If the Board **does not, within twenty-one days** from the date of receipt of a valid requisition in regard to any matter, proceed to call a meeting

❖ आगे इसमें कहा गया है कि 'कंपनी द्वारा ईजीएम बुलाने के लिए नोटिस की अवधि (कानून के अनुसार 21 दिन) के भीतर कदम उठाने में विफलता, 11 सितंबर 2021 को हमारे ईजीएम (अनुरोध) को नोटिस करने में देरी और एक्सचेंजों को हमारे सितंबर के पत्र को नोटिस करने में विफलता के साथ मिलकर, हमें कंपनी के इस ईजीएम के लिए कॉल करने के लिए शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष एक याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया है।

8. **29.09.2021** को इन्वेस्को ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई में जी के खिलाफ याचिका एक याचिका दायर करके पहली मिसाइल दागी। याचिका **कंपनी अधिनियम 2013** की धारा **98** और **100** के तहत दायर की गयी थी। धारा **98** एनसीएलटी को एक **असाधारण आम सभा** की बैठक बुलाने का आदेश देने का अधिकार देती है और धारा **100** एक शेयर धारक को एक ईजीएम का अनुरोध करने की शक्ति देती है, जिसके पास **एक-दसवें** से भी कम चुकता पूंजी शेयर पूंजी नहीं है।

9. धारा **98** इस प्रकार है

यदि किसी कारण से कंपनी की बैठक बुलाना अव्यावहारिक है, वार्षिक आम बैठक के अलावा, किसी भी तरीके से कंपनी की बैठक बुलाई जा सकती है या कंपनी की बैठक आयोजित करने या आयोजित करने के तरीके से इस अधिनियम या कंपनी के लेखों द्वारा निर्धारित, ट्रिब्यूनल या स्वप्रेरणा से या कंपनी के किसी निदेशक या सदस्य के आवेदन पर, जो वोट देने का हकदार होगा।

11. धारा **100** इस प्रकार है

- 1) बोर्ड जबभी उचित समझे कंपनी की एक **असाधारण आम बैठक** बुला सकता है।
- 2) बोर्ड द्वारा की गयी **मांग** पर
 - (ए) शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के मामले में, मांग की प्राप्ति की तारीख को रखने वाले सदस्यों की संख्या, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दसवें से कम नहीं के रूप में उस तिथि को मतदान का अधिकार होता है।
- 3) उप-धारा (2) के तहत की गयी **मांग** उन मामलों को निर्धारित करेगी जिनके लिए बैठक बुलाई जानी है, और मांगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भेजे जायेंगे।
- (4) यदि बोर्ड किसी भी मामले के संबंध एक **वैध मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों** के भीतर नहीं करता है तो

for the consideration of that matter on a day not later than **forty-five days** from the date of receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisitionists themselves within **three months** from the date of the requisition.

11. As per media reports, the **Invesco petition** makes the following points justifying the invocation of **Section 98** and **Section 100** of the **Companies Act 2013** for calling an **EGM**. It alleged that not convening the EGM was a deliberate and oppressive act by Zee. It, however, did not invoke provisions “Section 241” of Cos Act on oppression of minority shareholders.

- ❖ *Serious financial trouble since 2019, as admitted by the founder promoter, Mr Subhash Chandra, in his public letters of January 2019 and August 2019.*
- ❖ *Resignation of three Directors of the Company in November 2019 raising serious issues around corporate governance and capital allocation of the company. (Note: the three Directors were Mr Subodh Kumar and Ms Neeharika Vohra. As per the regulatory filing, they had raised concerns on large scale advances given to other media companies of the Essel Group, including Dish T.V. and Siticable, and for advances for film production). Another Director Mr Sunil Sharma resigned following the sale of shares by the Essel Group and consequent Board reconstitution)*
- ❖ *SEBI's letter to Zee in June 2021 flagging various alleged irregularities, including outstanding dues from related parties without a clear recovery plan; comfort letters issued by the Directors without informing the Board and corrective action required in systems and processes with regard to documentation of advances.*
- ❖ *Invesco sought the removal of some Directors, including the Managing Director Mr Punit Goenka. It sought to induct six new directors.*

12. At the preliminary hearing held on **September 30, 2021**, the senior counsels for Invesco and OFI Global made the following points

- ❖ That shareholders have an absolute unfettered right to call an **Extraordinary General Body Meeting**. The counsel stated that he represented a foreign fund and did not have addresses and

उस मामले पर विचार करने के लिए **45 दिन** बाद में एक बैठक बुलाने के लिए बढ़े। मांग की तारीख से **तीन महीने** के भीतर मांगकर्ता स्वयं बैठक बुला सकते हैं और आयोजित कर सकते हैं।

11. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार **इन्वेस्को याचिका कंपनी अधिनियम 2013** की **धारा 98** और **धारा 100** को **ईजीएम** बुलाने के उचित ठहराते हुए निम्नलिखित बिंदु बनाती है। इसमें आरोप लगाया गया कि ईजीएम का आयोजन नहीं करना जी द्वारा एक जानबूझकर और दमनकारी कार्य था। हालांकि, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के उत्पीड़न पर कंपनी अधिनियम की धारा 241 के प्रावधानों को लागू नहीं किया।

- ❖ **2019 के बाद से गंभीर वित्तीय संकट, जैसा कि संस्थापक प्रमोटर श्री सुभाष चंद्रा ने जनवरी 2019 और अगस्त 2019 के अपने सार्वजनिक पत्रों में स्वीकार किया है।**
 - ❖ **नवंबर 2019 में कंपनी के तीन निदेशकों का इस्तीफा कॉरपोरेट प्रशासन और कंपनी के पूंजी आवंटन के आसपास गंभीर मुद्दों को उठा रहा है। (नोटः तीन निदेशक श्री सुबोध कुमार और सुश्री निहारिका बोहरा थे। नियामक फाइलिंग के अनुसार उन्होंने डिश टीवी और सिटी केबल सहित एक्सेल समूह की अन्य मीडिया कंपनियों को दिये गये बड़े पैमाने पर अग्रिम और फिल्म निर्माण के लिए अग्रिमों पर चिंता व्यक्त की थी। एक अन्य निदेशक श्री सुनील शर्मा ने एसेल समूह द्वारा शेयरों की बिक्री और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड के पुर्नगठन के बाद इस्तीफा दे दिया।**
 - ❖ **जून 2021 में जी को सेबी का पत्र विभिन्न कथित अनियमितताओं को चिन्हित करता है, जिसमें स्पष्ट वसूली योजना के बिना संबंधित पक्षों से बकाया देय राशि शामिल है; निदेशकों द्वारा बोर्ड को सूचित किये बिना जारी किये गये आराम पत्र और अग्रिमों के दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई।**
 - ❖ **इन्वेस्को ने प्रबंध निदेशक श्री पुनीत गोयनका सहित कुछ निदेशकों को हटाने की मांग की। इसने छह नये निदेशकों को शामिल करने की भी मांग की है।**
12. **30 सितंबर 2021** को हुई आरंभिक सुनवाई में, **इन्वेस्को** और **ओएफआई ग्लोबल** के वरिष्ठ वकीलों ने निम्नलिखित बिंदु बताये:
- ❖ शेयरधारकों के पास **असाधारण आम सभा** की बैठक बुलाने का पूर्ण अधिकार है। वकील ने कहा कि वह एक

details of approximately two and a half lakh public shareholders.

- ❖ But it expressly stated that **Invesco** wanted Mr Punit Goenka to go as the Managing Director of the because the company is not being run by him for the benefit of shareholders.
 - ❖ With **96%** of the share with the public, there is no vested entrenched right in Mr Goenka or anyone else to run the company.
 - ❖ Quoting **Section 100** of the Companies Act and relying on the LIC Escorts case, the counsel stated no reason need be given to call an EGM as long as the 10% threshold is met.
 - ❖ Instead of calling an EGM, **Zee** announced the merger with **Sony**, the apprehension of **Invesco** was that the Board would not call an EGM.
13. In reply, the Senior Counsel for **Zee** stated that the meeting of the company"s independent directors was taking place on the same day-**September 30, 2021**. The decision that was taken would be suitably communicated.
 14. As per media reports, NCLT was not satisfied with the response by Zee and said the Board cannot deny calling an EGM when a **17%** shareholder has requested it. There is no specific format for a requisition except that the **10%** threshold should be crossed. *The NCLT is reported to have stated it would be a travesty of justice if their right to requisition is denied.*
 15. Finally, the NCLT adjourned the hearing to **4 October 2021**, directing that the **Zee Board should positively consider the request by Invesco and OFI**. As per the Press Trust of India, the NCLT directed the company to communicate the decisions of the Board after the NCLT meet.
 16. While a copy of the order actually passed is awaited, quite curiously, a **Zee** owned newspaper **DNA** claimed on **September 30, 2021** that "no such order has been passed by NCLT and that media reports on ZEE EGM were misleading and baseless. The company will continue to take all the actions needed in the interest of the shareholders and as per the law."
 - ❖ Within **24 hours** of the NCLT Interim Order, **Zee Board** rejected the demand of Invesco on primarily highly technical grounds. The **Release**

विदेशी फंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास लगभग ढाई लाख सार्वजनिक शेयरधारकों के परे व विवरण नहीं हैं।

- ❖ लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **इन्वेस्को** चाहता था कि श्री पुनीत गोयनका को प्रबंध निदेशक के रूप में जाना चाहिए क्योंकि कंपनी अपनी शेयरधारकों के लाभ के लिए उनके द्वारा नहीं चलाई जा रही है।
 - ❖ जनता के साथ **96%** हिस्सेदारी के साथ कंपनी चलाने के लिए श्री गोयनका या किसी और के पास कोई निहित अधिकार नहीं है।
 - ❖ कंपनी अधिनियम की **धारा 100** का हवाला देते हुए और एलआईसी एस्कॉर्ट्स मामले पर भरोसा करते हुए, वकील ने कहा कि जब तक **10%** की सीमा पूरी हो जाती है तब तक ईजीएम बुलाने का कोई कारण नहीं बताया जाना चाहिए।
 - ❖ ईजीएम बुलाने के बजाय **जी** ने **सोनी** के साथ विलय की घोषणा की, **इन्वेस्को** को आशंका थी कि बोर्ड ईजीएम नहीं बुलायेगा।
13. जवाब में **जी** के वरिष्ठ वकील ने बताया कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक इसी दिन **30 सितंबर 2021** को हो रही थी, उसमें जो भी निर्णय लिया गया उसे उपयुक्त रूप से सूचित किया जायेगा।
 14. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एनसीएलटी जी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था और कहा कि जब **17%** शेयरधारकों ने अनुरोध किया है तो बोर्ड ईजीएम बुलाने से इंकार नहीं कर सकता है। मांग के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है सिवाय इसके कि **10%** सीमा को पार किया जाना चाहिए। **बताया जाता है कि एनसीएलटी ने कहा है कि अगर मांग के उनके अधिकार से इंकार किया जाता है तो यह न्याय का मजाक होगा।**
 15. अंत में एनसीएलटी ने **4 अक्टूबर 2021** को मुनवाई स्थगित कर दी, यह निर्देश दिया कि **जी बोर्ड** को **इन्वेस्को** और **ओएफआई** के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार एनसीएलटी ने कंपनी कंपनी को एनसीएलटी की बैठक के बाद बोर्ड के फैसले को भेजने का निर्देश दिया।
 16. हालांकि वास्तव में पारित आदेश की एक प्रति का काफी उत्सुकता से इंतजार है, **जी** के स्वामित्व वाले समाचार पत्र **डीएनए** ने **30 सितंबर 2021** को दावा किया है कि **'एनसीएलटी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, और ईजीएम पर मीडिया रिपोर्ट भ्रामक और निराधार है। कंपनी शेयरधारकों के हित में और कानून के मुताबिक सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगी।**
 - ❖ एनसीएलटी अंतरिम आदेश के **24 घंटे** के भीतर **जी बोर्ड** ने मुख्य रूप से अत्यधिक तकनीकी आधार पर इन्वेस्को की

to the Stock Exchanges dated **01.10.2021** states in **Paras 7 and 8** as under:

- ◆ **Para 7** At its meeting held on **1 October 2021**, the Board considered the **Requisition Notice**. Earlier, the Board obtained written legal advice from the company's counsel and **independent legal advice** from eminent former judges of the Supreme Court and senior corporate lawyers. After considering the unanimous advice received about the legal validity of the **Requisition Notice**, the Board deliberated and unanimously concluded that the **Requisition Notice** is not valid, as it suffers from multiple **legal infirmities**, which are summarised in the **Annexure** to this communication.
- ◆ **Para 8**. Accordingly, in the company's best interests as a whole, including all its shareholders and stakeholders, we express our inability to convene the **EGM** on the lines requisitioned by you.
- ◆ Subsequently Zee filed a writ petition challenging the Invesco petition in the **Bombay High Court**. This is still to be fixed for hearing.
- ◆ When **NCLT** directed Zee to file a counter to the Invesco petition and gave it **48 hours** to do so, Zee filed an appeal to the **National Company Law Appellate Tribunal**. Interestingly both the **NCLT** and **NCLAT** hearings are fixed for hearing on **October 7, 2021**.
- ◆ Simultaneously the Zee Founder launched a video campaign casting doubts on the "motives" of Invesco and even talking of some Indian backing (reference to Ambanis) and even talking darkly of a Chinese "reluctance" to allow the merger to go through!

COMMENT

The sword of litigation will now hang over the timeline of the term sheet between Zee and Sony. One thing is clear that Invesco is not as such opposed to the merger. It took an additional stake

मांग को खारिज कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को दिनांक **01.10.2021** को जारी विज्ञप्ति के पैरा 7 और 8 में निम्न बातें बतायी गयी हैं:

- ◆ **पैरा 7, 1 अक्टूबर 2021** को हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने मांग नोटिस पर विचार किया। इससे पहले बोर्ड ने कंपनी के वकील से लिखित कानूनी सलाह और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ कॉर्पोरेट वकीलों से स्वतंत्र कानूनी सलाह प्राप्त की। मांग नोटिस की कानूनी वैधता के बारे में प्राप्त सर्वसम्मत सलाह पर विचार करने के बाद बोर्ड ने विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि मांग नोटिस वैध नहीं है, क्योंकि यह कई कानूनी कमजोरियों से ग्रस्त है जिन्हें इस संचार अनुबंध में संक्षेपित किया गया है।
- ◆ **पैरा 8**, तदनुसार कंपनी के सभी शेयरधारकों और हितधारकों सहित, समय रूप से कंपनी के सर्वोत्तम हित में हम आपके द्वारा आपेक्षित तर्ज पर **ईजीएम** आयोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं।
- ◆ इसके बाद जी ने मुंबई उच्च न्यायालय में इन्वेस्को की याचिका को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर किया। इस पर सुनवाई की जानी बाकी है।
- ◆ जब एनसीएलटी ने जी को इन्वेस्को याचिका का जवाब दाखिल करने निर्देश दिया और नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने के लिए उसे **48 घंटे** का समय दिया। दिलचस्प बात यह है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों की सुनवाई की तारीख **7 अक्टूबर 2021** तय की गयी है।
- ◆ इसके साथ ही जी फाउंडर ने इन्वेस्को के 'उद्देश्यों' पर संदेह जताते हुए एक वीडियो अभियान शुरू किया है और यहां तक कि कुछ भारतीय समर्थन (अंबानी के संदर्भ में) की भी बात कर रहे हैं और यहां तक कि विलय की अनुमति देने के लिए चीनी 'अनिच्छा' के बारे में भी बात कर रहे हैं।

टिप्पणी

जी और सोनी के बीच टर्म शीट की टाइमलाइन पर अब मुकदमों की तलवार लटक जायेगी। एक बात तो साफ है कि इन्वेस्को इस तरह के विलय के खिलाफ नहीं है। इसने 2019 में 400 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर अतिरिक्त हिस्सेदारी ली। भले ही विलय की घोषणा

in 2019 at an average price of Rs. 400 a share. Even though there has been massive stock market excitement since the merger was announced, the price on in the NSE in morning session was Rs. 296, which means if Invesco were to sell out, it would incur enormous losses.

The critical concern of Invesco is corporate governance which is clearly spelt out in the last paragraph of its letter of September 23, 2021. Invesco clearly feels that this needs to be improved. In the hearing held on September 29, 2021, it clearly trained its fire on the Managing Director, Mr Punit Goenka and sought his explicit exit.

There is some speculation that Invesco wants an independent Board that is not bound down to a four per cent Promoter shareholder and will negotiate even better terms with Sony. It may even find another strategic or financial investor.

More clarity will emerge at the next NCLT hearing on October 4, 2021.

के बाद से बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में उत्साह रहा हो, लेकिन एनएसई में 28 सितंबर 2021 को समापन मूल्य केवल 309.15 रुपये था, इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्को इसको बेचने की कोशिश करे तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा।

इन्वेस्को की महत्वपूर्ण चिंता कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसे 23 सितंबर 2021 के अपने पत्र के अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इन्वेस्को को स्पष्ट रूप से लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। 29 सितंबर 2021 को हुई सुनवाई में इसने प्रबंध निदेशक श्री पुनीत गोयनका पर अपनी आग को स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित किया और स्पष्ट रूप से बाहर निकलने को कहा।

कुछ अटकलें हैं कि इन्वेस्को एक स्वतंत्र बोर्ड चाहता है जो चार प्रतिशत प्रमोटर शेयरधारक के लिए बाध्य नहीं है और सोनी के साथ और भी बेहतर शर्तों पर बातचीत करेगा। यह एक और रणनीतिक या वित्तीय निवेशक भी ढूँढ सकता है।

4 अक्टूबर 2021 को एनसीएलटी की अगली सुनवाई में और स्पष्टता आयेगी।

STOP PRESS

MEDIA BEAT

ZEE - INVESCO CASE LATEST UPDATE

“In its order dated October 7, 2021, NCLAT directed NCLT to give sufficient and reasonable time to file its reply to the Invesco petition asking NCLT to direct Zee to hold an EGM to decide on its chosen panel of Directors. After the reply is filed, and hearing both parties, NCLT can proceed further.”

छपते-छपते

मीडिया बीट

जी-इन्वेस्को मामला नवीनतम अपडेट

‘7 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश में, एनसीएलटी ने एनसीएलटी को इन्वेस्को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त और उचित समय देने का निर्देश दिया, जिसमें एनसीएलटी को जी को अपने चुने हुए निदेशकों के पैनल पर निर्णय लेने के लिए ईजीएम आयोजित करने का निर्देश देने के लिए कहा गया था। जवाब दाखिल होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनसीएलटी आगे की कार्रवाई कर सकता है।’

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

... You Know What You are doing

But Nobody Else Does



MAGAZINE

ADVERTISE NOW!

Contact:

Mob.: +91-7021850198

Tel.: +91-22-6216 5313

Email: scat.sales@nm-india.com

A.3 CONTENT SYNERGIES OF THE MERGER

Zee has a total of approximately 50 channels. It has a powerful ZEE 5 app, and the channels are currently telecast in 170 countries with an estimated 1.3 billion viewers. It has over 4200 movie titles. Its library has over 2,50,000 hours of T.V. content. It is also into music and the creation of animation software.

Sony has over 25 channels which are partly different to Zee channels. It is strong in Sports with ten channels. It has a regional presence in Marathi and Bangla and also has a powerful Sony Liv app. Its main Hindi channel has powerful content like Kaun Banega Crorepati and Super Dancer.

A combined subscription drive should provide it with higher revenues. A more extensive portfolio of 75 plus channels will give it additional advertisement muscle.

Cost savings are still to be worked out. There will have to be staff rationalisation.

The entire process, including regulatory approvals from Government/NCLT and Competition Commission, will take six-12 months in view of the legal dispute with Invesco.

COMMENT:

Once the merger is completed with all regulatory approvals, it will pose tough competition to Disney Star and even regional majors like Sun T.V. This can only mean welcome news for its millions of viewers. So, to answer who the winner will be, everyone, especially the customer, will have a plethora of content choices. Zee gets badly needed capital. Sony receives access to an entire and impressive body of programming content of Zee and an impressive library.

Even though Invesco has asked for reconstitution of the Board, the tremendous price rise from Rs. 175 to the present rate of Rs. 310 benefits Invesco. Two "lucky new investors," namely Mr Rakesh Jhunjhunwala, picked up nearly 5 million shares for Rs. 110.22 crores of Zee at Rs. 220.44 a share earlier in September, and BofA Securities bought 4.86 million shares for Rs. 115 crores at Rs. 236.20 a share have made enormous profits in just 10 days. So, everyone has benefitted!

ए.3 विलय की कंटेंट सिनर्जी

जी के पास कुल 50 चैनल हैं। इसके पास एक शक्तिशाली जी 5 ऐप है और चैनल वर्तमान में अनुमानित 1.3 बिलियन दर्शकों के साथ 170 देशों में प्रसारित होता है। इसमें 4000 से अधिक मूवी टाइटल हैं। इसके लाइवरी में 2,50,000 घंटे से अधिक की टीवी सामग्री है।

यह संगीत और एनीमेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण में भी है।

सोनी के पास 25 से अधिक चैनल हैं जो जी के चैनलों से आंशिक रूप से भिन्न हैं। यह दस चैनलों के साथ स्पोर्ट्स में मजबूत है। इसकी मराठी और बंगाली में क्षेत्रीय उपस्थिति है और इसके पास एक शक्तिशाली सोनीलिव ऐप है। इसके मुख्य हिंदी चैनल में कौन बनेगा करोड़पति और सुपर डॉसर जैसे दमदार कंटेंट हैं।

एक संयुक्त सब्सक्रिप्शन अभियान को इसे उच्च राजस्व प्रदान करना चाहिए। 75 से अधिक चैनलों का अधिक व्यापक पोर्टफोलियो इसे अतिरिक्त विज्ञापन पेशी देगा।

लागत बचत पर अभी काम करना बाकी है। कर्मचारियों को युक्तिसंगत बनाना होगा।

सरकार/एनसीएलटी और प्रतिस्पर्धा आयोग से विनियामक अनुमोदन सहित पूरी प्रक्रिया में 6 से 12 महीने लगेंगे।

टिप्पणी

एक बार जब विलय सभी नियामक अनुमोदनों के साथ पूरा हो जाता है तो यह डिज्नी स्टार और यहां तक सन टीवी जैसे क्षेत्रीय बड़ी कंपनियों को टक्कर देगा। इसका मतलब केवल इसके लाखों दर्शकों के लिए स्वागत योग्य समाचार हो सकता है। तो अब इसका विजेता कौन रहा, तो इसका उत्तर है सब, विशेष रूप से ग्राहक, जिनके पास अब बहुत सारे चैनलों का विकल्प होगा। जी को जहां वेहत आवश्यक पूंजी प्राप्त होगा। सोनी को जी की कार्यक्रम सामग्री की संपूर्ण और प्रभावशाली वॉडी और एक मजबूत लाइवरी तक पहुंच प्राप्त होगी।

भले ही इन्वेस्को ने बोर्ड के पुर्नगठन के लिए कहा है लेकिन 175 रुपये से मौजूदा 310 रुपये की जबरदस्त कीमत इन्वेस्को को फायदा पहुंचाती है। दो भाग्यशाली निवेशक यानी श्री राकेश झुनझुनवाला ने सितंबर में पहले 220.44 रुपये प्रति शेयर पर जी के 110.22 करोड़ रुपये में लगभग 5 मिलियन शेयर खरीदे और बोफा सिक्योरिटीज ने 236.20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 115 करोड़ रुपये में 4.86 मिलियन शेयर खरीदे और सिर्फ 10 दिनों में भारी मुनाफा कमाया। इस तरह सभी को फायदा हुआ।

B. ONLINE GAMING UNDER THREAT?

1. The Indian Online Gaming Sector reached **US\$1.027 billion** in 2020, a growth of **~17.3%** from **US\$543 million** in 2016. It is expected to reach **US\$2 billion** by 2023. India is the **fourth largest** online gaming market globally. Online gamers in India are estimated to grow from **360 million** in 2020 to **510 million** in 2022. It is estimated that over **400** gaming start-ups are running at present.
2. A **June 2021 KPMG Report** states: *We envisage the online gaming segment to be among the most significant segments of M & E industry in years to come, garnering a share of both time and wallet of the Indian digital billion.*"
3. A key challenge for the Sector is a facilitative and robust regulatory and legal environment to help the business grow to its true potential in the coming years.
4. Another critical concern is GST concerns. The classification of whether a game forms a '**game of skill**' or a '**game of chance**' has had tax implications on business operations. A **game of chance** attracts a higher GST rate of tax vis-à-vis a **game of skill**. The same classification is used by state legislatures to curb online gaming.
5. Three recent **legal developments** show how various moralistic factors can impede this sunshine industry's growth despite the recognised potential of online gaming.
6. On **21 September 2021**, the Karnataka Assembly amended the **Karnataka Police Act** to ban all forms of **online gaming** holding as per objects and reasons of the amendment that it is intended to "strengthen" provisions of the **Karnataka Police Act** to make gambling a cognisable and non-bailable offence and "include the use of cyberspace including computer resources or any communication device as defined in the **Information Technology Act, 2000** in the process of gaming to curb the menace of gaming through the internet, mobile apps". The amended law prescribed a **three-year** jail term for gambling instead of one year and a fine of Rs **One lakh**. The law exempted only **bets on horse races** from the purview of gambling.
7. The Karnataka Home Minister was quoted as

बी. खतरे में ऑनलाइन गेमिंग?

1. भारतीय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र **2020** में **1.027** बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया, जो **2016** में **543** मिलियन अमेरिकी डॉलर से **17.3%** की वृद्धि दर्शाता है। इसके **2023** तक **2** बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत विश्वस्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग बाजार है। भारत में ऑनलाइन गेमर्स के **2020** में **360** मिलियन से बढ़कर **2022** तक **510** मिलियन होने का अनुमान है। अनुमान है कि वर्तमान में **400** से अधिक गेमिंग स्टार्टअप चल रहे हैं।
2. **जून 2021 की केपीएमजी रिपोर्ट** में कहा गया है: *हम आने वाले वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट को एम एंड ई उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में शामिल करने की उम्मीद करते हैं, जो भारत के लिए बिलियन डालर हासिल करने वाला साबित होगा।*
3. आने वाले वर्षों में व्यवसाय को उसकी वास्तविक क्षमता तक बढ़ने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती एक सुविधाजनक और मजबूत नियामक और कानूनी वातावरण है।
4. एक और महत्वपूर्ण चिंता जीएसटी की चिंता है। यह वर्गीकरण कि क्या कोई खेल '**कौशल का खेल**' या '**मौके का खेल**' बनाता है, का व्यवसाय संचालन पर टैक्स संबंधी प्रभाव पड़ा है। **मौके का खेल, कौशल के खेल** की तुलना में टैक्स की उच्च जीएसटी दर आकर्षित करती है। ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा समान वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है।
5. तीन हालिया **कानूनी घटनाक्रम** बताते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की मान्यता प्राप्त क्षमता के बावजूद विभिन्न नैतिक कारक इन उभरते उद्योग के विकास को कैसे बाधित कर सकते हैं।
6. **21 सितंबर 2021** को **कर्नाटक विधान सभा** ने वस्तुओं और संशोधन के कारणों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग होल्डिंग के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने के लिए **कर्नाटक पुलिस अधिनियम** में संशोधन किया, जिसका उद्देश्य जुआ को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए और इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से गेमिंग के खतरे को रोकने के लिए गेमिंग की प्रक्रिया में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000** में परिभाषित कंप्यूटर संशोधनों या किसी संचार उपकरण सहित साइबर स्पेस का उपयोग शामिल करें। संशोधित कानून में जुए के लिए एक साल के बजाय **तीन साल** की जेल और **एक लाख** के जुर्माने का प्रावधान है। कानून ने केवल **घुड़दौड़ पर दांव** लगाने को जुए के दायरे से छूट दी है।
7. कर्नाटक के गृहमंत्री को यह दावा करते हुए उद्धृत किया गया था,

claiming,"*there is a lot of gambling happening using electronic devices, and this has to be controlled.*" The new Karnataka Chief Minister felt "*major gambling is happening in an organised way in many places.*"

8. The **Internet and Mobile Association of India (IAMAI)**, in a statement, said that the Bill *appears to have been drafted without considering the various legal and constitutional positions as it includes a wide definition of 'gaming' and is against multiple judgements by the Supreme Court and High Courts. Further, it makes no distinction between games of skill and of chance.*
9. Karnataka itself has been home to more than **91 gaming companies** and developers, which employ about **4,000** people, said Mr Biren Ghose, Chairman - **CII National AVGC sub-committee**. "*The ban would impact Indian online gaming companies, while consumers would switch to games from other geographies. Further, this would affect the brands that have been built up with considerable investments over the last few years,*" he added.
10. In a letter to the Karnataka Chief Minister, Mr Praveen Khandelwal, Secretary-General of the Confederation of All India Traders, stated that *a game of chance is pure gambling, which is addictive and should be dealt with adequate legal procedures. On the other hand, a game of skill enables gamers to monetise their gaming talents and finesse.*
11. Very recently, the **Madras High Court** passed a very detailed judgment in **Junglee Games vs State of Tamil Nadu in WP 18022/Ors dated August 3, 2021** struck down the **February 2021** amendment to the **Tamil Nadu Gaming Act** that prohibited betting and wagering on all forms of online gaming.
12. In **February 2021**, the Tamil Nadu government amended the **Tamil Nadu Gaming Act, 1930 ('the Gaming Act')**, by passing the **Tamil Nadu Gaming and Police Laws (Amendment) Act, 2021 ('the Amending Act')**. **Section 3(b)** of the Amending Act redefined '**gaming**' to include any game involving wagering or betting in person or cyberspace, except a lottery. It prohibited **all forms of games conducted in cyberspace**, regardless of whether it was a game of mere skill or a game of chance, removing the exemption for '**games of mere skill**' in the **Gaming Act**. Additionally, the **Amending Act** introduced **Section**

'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके बहुत अधिक जुआ हो रहा है और इसे नियंत्रित करना होगा।' कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि *कई जगहों वड़ा जुआ संगठित तरीके से हो रहा है।*

8. **इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई)** ने एक बयान में कहा है कि *विल विभिन्न कानूनी और संवैधानिक पदों पर विचार किये बिना तैयार किया गया प्रतीत होता है क्योंकि इसमें गेमिंग की व्यापक परिभाषा शामिल है और यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई फैसले के खिलाफ है। इसके अलावा, यह कौशल और मौके के खेल के बीच कोई अंतर नहीं करता है।*
9. **सीआईआई नेशनल एवीजीसी** उप-समिति के अध्यक्ष श्री वीरेन घोष ने कहा, कर्नाटक में है **91 से अधिक गेमिंग कंपनियां** और डेवलपर्स हैं जिनमें लगभग **4000** लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि *'प्रतिबंध भारतीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को प्रभावित करेगा, जबकि उपभोक्ता अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से गेम पर स्विच करेंगे। इसके अलावा यह उन ब्रांडों को प्रभावित करेगा जो पिछले कुछ वर्षों में काफी निवेश के साथ बनाये गये हैं।*
10. कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे गये एक पत्र में 'अखिल भारतीय व्यापारियों के परिषद के महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि *मौके का खेल शुद्ध जुआ है, जो नशे की लत है और इसे पर्याप्त कानूनी प्रक्रियाओं से निपटा जाना चाहिए। दूसरी ओर कौशल का खेल गेमर्स को अपनी गेमिंग प्रतिभा और चालाकी से कमाई करने में सक्षम बनाता है।*
11. हाल ही में **मद्रास उच्च न्यायालय** ने **डब्ल्यूपी 18022/0आरएस जंगली खेलों बनाम तमिलनाडु राज्य में 3 अगस्त 2021** को एक बहुत विस्तृत निर्णय पारित किया, जिसमें **तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में फरवरी 2021** के संशोधन को रद्द कर दिया गया था जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के सभी रूपों पर सट्टेबाजी और दांव लगाना प्रतिबंधित कर दिया।
12. **फरवरी 2021** में **तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 (संशोधन अधिनियम)** को दरकिनार करते हुए **तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, 1930 (द गेमिंग एक्ट)** में संशोधन किया। **संशोधन अधिनियम की धारा 3 (बी)** ने गेमिंग को एक लॉटरी को छोड़कर, व्यक्तिगत रूप से या **साइबर स्पेस में दांव लगाने या सट्टेबाजी से जुड़े किसी भी खेल को शामिल करने** के लिए गेमिंग को परिभाषित किया है। इसने साइबर स्पेस में आयोजित सभी प्रकार के खेलों को प्रतिबंधित कर दिया, चाहे वह केवल कौशल का खेल या मौका का खेल, गेमिंग अधिनियम में 'मात्र कौशल' के खेल के लिए छूट को हटा दिया। इसके अतिरिक्त

3-A to prohibit wagering or betting in cyberspace by playing rummy, poker, or any other game, punishable with imprisonment extending to **two years** for anyone playing or providing such activities.

13. **Section 11** of the **Amending Act** also included games of '**mere skill**' into the fold of offences if such games were played for wager, bet, money or other stakes. This, in fact, went beyond the **Tamil Nadu Gaming and Police Laws (Amendment) Ordinance 2020**, which did not remove the exemption to '**games of mere skill**' in **Section 11** of the original **1930 Act** and would not have covered wagers and prizes on games such as (**online and offline**) chess.

14. After a series of exhaustive arguments by the Petitioners and Respondent, the Madras High Court struck down **Part II** of the **Amending Act** on **four grounds**:

- ❖ **Firstly**, the impugned part and its **blanket ban on gaming for money** were excessive, disproportionate, unreasonable, and manifestly arbitrary.
- ❖ **Secondly**, the **enactment** was **violative of Article 19(1)(g)** of the Constitution.
- ❖ **Thirdly**, that the **enactment** was not within the scope of **legislative competence** under **Entry 34 of List II of Schedule VII** to the Constitution; and
- ❖ **Fourthly**, that the **enactment** was **inconsistent and irreconcilable** with established precedents.

15. The Court further held:

- ❖ While interpreting the scope of "**gambling**" and "**gaming**," the Court saw that the terms involve activities whose outcomes depend predominantly on an **element of chance** [Para 97].
- ❖ On the other hand, an activity is regarded as a game of "**skill**" if the consequences are guided more by **skill** than chance.
- ❖ The High Court held various online games such as poker and rummy are **games of skill** as they needed knowledge, skill, and memory [Para 114].
- ❖ However, the expanded definition of "**gaming**" under **Section 3(b)** and the sweeping ambit of **Section 3-A** of the **Amending Act** encompassed all sporting/gaming activities

संशोधन अधिनियम ने रम्मी, पोकर या कोई अन्य खेल खेलकर साइबर स्पेस में दांव लगाने या सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने के लिए **धारा 3-ए** की शुरुआत की इस तरह की गतिविधियों को खेलने या प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए **दो साल** तक कारावास की सजा दी जा सकती है।

13. **संशोधन अधिनियम** की **धारा 11** में **मात्र कौशल** के खेल भी अपराधों की तह में शामिल है, अगर इस तरह के खेल दांव, दांव पैसे या अन्य दांव के लिए खेले जाते हैं। यह वास्तव में **तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020** से आगे निकल गया, जिसने मूल **1930 अधिनियम** की **धारा 11** में **मात्र कौशल के खेल** की छूट को नहीं हटाया और (**ऑनलाइन या ऑफलाइन**) शतरंज जैसे खेलों पर दांव और पुरस्कारों को कवर नहीं करता है।

14. याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों की एक श्रृंखला के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने **संशोधन अधिनियम** के **भाग 2** को **चार आधारों** पर रद्द कर दिया:

- ❖ **सबसे पहले**, पैसे के लिए **जुआ खेलने पर आक्षेपित भाग और इसका व्यापक प्रतिबंध** अत्यधिक, अनुपातहीन, अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना था।
- ❖ **दूसरे**, यह **अधिनियम** संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(जी)** का **उल्लंघन** था।
- ❖ **तीसरा**, यह **अधिनियम** संविधान की **अनुसूची 7 की सूची 2** की **प्रविष्टि 34** के तहत **विधायी क्षमता** के दायरे में नहीं था और
- ❖ **चौथा** यह कि **अधिनियम** स्थापित उदाहरणों के साथ **असंगत और बेमेल** था।

15. न्यायालय ने आगे कहा:

- ❖ **जुआ और गेमिंग** के दायरे की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने देखा कि शर्तों में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिनके परिणाम मुख्य रूप से **अवसर के तत्व पर निर्भर करते हैं (पैरा 97)**।
- ❖ दूसरी ओर, एक गतिविधि को **कौशल** के खेल के रूप में माना जाता है यदि परिणाम संयोग से अधिक **कौशल** द्वारा निर्देशित होते हैं।
- ❖ उच्च न्यायालय ने पोकर और रम्मी जैसे विभिन्न ऑनलाइन खेलों को **कौशल का खेल** माना क्योंकि उन्हें, ज्ञान, कौशल और स्मृति की आवश्यकता थी। (**पैरा 114**)
- ❖ हालांकि, **धारा 3 (बी)** के तहत **गेमिंग** की विस्तारित परिभाषा और **संशोधन अधिनियम** की **धारा 3-ए** के व्यापक दायरे में सभी खेल/गेमिंग गतिविधियां (चाहे आभासी या भौतिक) शामिल हैं, यदि वे पुरस्कार/पैसे/हिस्सेदारी के लिए खेली जाती हैं।

(whether virtual or physical) if played for a prize/money/stake.

- ❖ The Court held that the **Amending Act** created a **legal fiction**, whereby even **games of skill**, which were otherwise permissible, would amount to an offence if any betting were involved, which turned "**the existing statute on its head**" [Paras 102-103].
- ❖ Therefore, the High Court found that the wording of the Amending Act was overbearing and excessive, since:
 - ◆ *A person may be gifted in card games, or another's talent may lie in word games. Rationally, such persons should be free to exploit their skills; only reasonable restrictions that do not entirely blunt their chance to show off or make a living out of their skills may be permissible. The sweeping wording of Section 3-A of the amended Act of 1930, coupled with the expansive definition of "gaming" injected there, cuts any chance of displaying skill in any game on the virtual mode if any stakes, however little, are involved.* **Para 102.**
 - ◆ *"Indeed, section 11 of the amended Act turns the existing statute on its head, as the Petitioners complain. What was once the exemption or escape provision has now been given the **most claustrophobic stranglehold** and has the possibility of bringing about the most ridiculous and unwanted results if applied in letter and spirit."* **Para 103.**

16. Immediately after the judgment was delivered, the Tamil Nadu Law Minister said Government would formulate new legislation to ban online gaming platforms. *"Although Government put forward its views on the ban on online games, the High Court said that the Government did not specify enough reasons when the law was made and without formalising the rules, online gaming cannot be banned."*
17. Despite such a detailed and persuasive judgment of the Madras High Court in **August 2021**, the Karnataka Assembly passed new amendments to the Karnataka Police Act on **22 September 2021**. The Bill states that "*games mean and include online games, involving all forms of wagering or betting,*

- ❖ न्यायालय ने माना कि **संशोधन अधिनियम** ने एक **कानूनी कल्पना** का निर्माण किया, जिससे **कौशल के खेल** भी, जो अन्यथा अनुमेय थे, यदि कोई सट्टेबाजी शामिल थी, तो अपराध की राशि होगी, जिसने मौजूदा **कानून को उसके सिर पर बदल दिया (पैरा 102-103)**।

- ❖ इसलिए, उच्च न्यायालय ने पाया कि संशोधन अधिनियम की शब्दावली दबंग और अत्यधिक थी, क्योंकि :

- ◆ *एक व्यक्ति ताश के खेल में उपहार दिया जा सकता है या दूसरे की प्रतिभा शब्द के खेल में निहित हो सकती है। तर्कसंगत रूप से, ऐसे व्यक्तियों को अपने कौशल का दोहन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, केवल उचित प्रतिबंध जो उनके कौशल को दिखाने या जीवनयापन करने के अवसर को पूरी तरह से कुंद नहीं करते हैं, अनुमेय हो सकता है। 1930 के संशोधित अधिनियम की धारा 3-ए का व्यापक शब्दांकन, वहां इजेक्शन की गई गेमिंग की विस्तृत परिभाषा के साथ वर्चुअल मोड पर किसी भी गेम में कौशल प्रदर्शित करने के किसी अवसर को कम करता है, यदि कोई दांव हालांकि थोड़ा सा शामिल है। पैरा 102*
- ◆ **वास्तव में, संशोधित अधिनियम की धारा 11** मौजूद कानून को उसके सिर पर रखती है, जैसाकि याचिकाकर्ता शिकायत करते हैं। जो कभी छूट या भागने के प्रावधान था, उसे अब **सबसे क्लॉस्ट्रोफोबिक स्ट्रगल** दिया गया है और इसमें सबसे हास्यापद और जो कभी छूट या भागने का प्रावधान था, उसे अब सबसे अधिक दयनीय पकड़ दिया गया है और यदि अक्षर और भावना में लागू किया जाए तो सबसे हास्यापद और अवांछित परिणाम लाने की संभावना है। पैरा 103

16. फैसला सुनाये जाने के तुरंत बाद, तमिलनाडु के कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून बनायेगी। *हालांकि सरकार ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध पर अपने विचार रखे, उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने पर्याप्त कारण निर्दिष्ट नहीं किये जब कानून बनाया गया था और नियमों को औपचारिक रूप दिये बिना, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।*
17. **अगस्त 2021** में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तरह के विस्तृत और प्रेरक निर्णय के बावजूद कर्नाटक विधानसभा ने **22 सितंबर 2021** को कर्नाटक पुलिस अधिनियम में नये संशोधन पारित किये। बिल में कहा गया है कि *‘गेम का मतलब है और इसमें ऑन*

including in the form of tokens valued in terms of the money paid before or after the issue of it, or electronic means and virtual currency, electronic transfer of funds in connection with any game of chance.” The Bill to amend the **Karnataka Police Act of 1963 does not include lottery, wagering, betting on horse races on any racecourse inside or outside the State.**

18. The newly passed Bill in the Karnataka Assembly includes using **cyberspace** (computer resources or any other communication device) as defined in the **Information Technology Act, 2000** in the process of gaming to curb **online gaming** and **gambling** through the internet and mobile apps. The Bill also enhances punishment extending to three years of punishment and a fine up to Rs 1 lakh. Punishment for the first offence will be 6 months imprisonment, a fine of Rs 10,000 and one year of imprisonment, and Rs 15,000 for the second one. In the third offence, punishment will be 18 months imprisonment and a fine of Rs 20,000. Those found aiding such **online gambling** will also be punished.
19. Karnataka government's push against **online gaming and gambling** can impact indigenously developed online gaming platforms such **Dream 11, Mobile Premium League, Games 24x7** and several others banning **online gaming and wagers and prizes that, if upheld by the Courts, could bring a death knell for the online gaming industry in Karnataka.**
20. Since this is a BJP ruled State, it will be interesting to watch whether other major BJP ruled States like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh will follow suit.
21. On **27.09.2021**, a single bench judgment of the **Kerala High Court in Head Digital Works Private Limited vs the State of Kerala** quashed an amendment to a Government notification dated **23.02.2021** issued under **Section 14A** of the **Kerala Gaming Act 1960** banning **online rummy** in the State. The Court held it was arbitrary and violative of the right to trade and commerce guaranteed under **Article 19(1) (g)** of the Constitution. The judgment stated:

❖ *Based on the considerations above, I go back to the issues identified in **Para 13** of this judgment. On the first issue of whether rummy is a game of mere skill, I hold on to the basis of the binding judgments of the Apex Court in*

लाइन गेम भी शामिल है जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाना और सट्टेबाजी शामिल है जिसमें टोकन के रूप में इसके जारी होने से पहले या बाद में भुगतान किये गये पैसे या इलेक्ट्रॉनिक साधन और आभासी मुद्रा, मौका के किसी भी खेल के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण शामिल है। **कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य के अंदर या बाहर किसी रेसकॉर्स पर लॉटरी, दांव लगाना, घुड़दौड़ पर दांव लगाना शामिल नहीं है।**

18. कर्नाटक विधानसभा में नये पारित विधेयक में इंटरनेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से **ऑनलाइन गेमिंग** और **जुआ** पर अंकुश लगाने के लिए गेमिंग की प्रक्रिया में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000** में परिभाषित **साइबरस्पेस** (कंप्यूटर संसाधन या कोई अन्य संचार उपकरण) का उपयोग करना शामिल है। विधेयक में तीन साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना को भी बढ़ाया गया है। पहली बार अपराध करने पर छह महीने की कैद, दस हजार रुपये का जुर्माना और एक साल की कैद और दूसरी बार **15** हजार रुपये तक की सजा होगी। तीसरे अपराध में **18** महीने की कैद और **20** हजार रुपये का जुर्माना होगा। ऐसे **ऑनलाइन जुआ** में सहायता करने वालों को भी दंडित किया जायेगा।
19. **ऑनलाइन गेमिंग** और **जुआ** के खिलाफ कर्नाटक राज्य सरकार का जोर स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे **ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेम्स 24x7**, और कई अन्य ऑनलाइन गेमिंग और दांव और पुरस्कारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि अगर अदालतों द्वारा बरकरार रखा जाता है तो कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए मौत की घंटी बजा सकता है।
20. चूंकि यह भाजपा शासित राज्य है इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख भाजपा शासित राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।
21. **27.09.2021** को **हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड** बनाम केरल राज्य में **केरल उच्च न्यायालय** के एकल पीठ के फैसले ने केरल **गेमिंग अधिनियम 1960** की धारा **14ए** के तहत जारी सरकारी अधिसूचना दिनांक **23.02.2021** में एक संशोधन को राज्य में ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने इसे मनमाना और **संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(जी)** के तहत गारंटीकृत व्यापार और वाणिज्य के अधिकार का उल्लंघन बताया। फैसले में कहा गया है कि
 - ❖ उपरोक्त विचारों के आधार पर मैं इस निर्णय के **पैरा 13** में पहचाने गये मुद्दों पर वापस जाता हूँ। पहले मुद्दे पर कि क्या

Satyanarayana and K.R. Lakshmanan (supra) and the statutory provisions contained in Sections 3 and 14 of the Kerala Act that Rummy is a game of mere skill. On the question of whether rummy is a game in which 'element of skill' is more predominant than the 'element of chance' and can be exempted from the provisions of the Act only by means of notification, I hold that even without a notification being issued under Section 14A, rummy remains to be a 'game of mere skill' as the word has been interpreted by the Hon'ble Supreme Court in Satyanarayana and K.R.Lakshmanan (supra).

COMMENT

This writer is of the view that there is a vast difference between gaming and gambling. Curiously, the Karnataka Assembly has allowed gambling on horse racing in Karnataka and tried to ban other gaming activities. That itself, it is given, is constitutionally impermissible. Another possibility could be model legislation allowing gaming but strictly regulating gambling by devising model legislation for adoption by the States.

C. WILL CABLE ADOPT BROADBAND TO REMAIN RELEVANT?

As per TRAI data for July 31, 2021, released on 23 September 2021, the total number of Broadband subscribers were 808 million subscribers, of which 784.59 million were Wireless Broadband subscribers provided by 455 operators. The balance of 24.01 million were Wireline Broadband subscribers:

Wireless Broadband - Top 5 Networks (98.77% of total market share of Wireless Broadband)

- ◆ Reliance Jio Infocomm Ltd (446.68 million).
- ◆ Bharti Airtel (201.77 million).
- ◆ Vodafone Idea (123.97 million).
- ◆ BSNL (24.26 million) and
- ◆ Atria Convergence (01.93 million)

रमी केवल कौशल का खेल है, मैं सत्यनारायण और के.आर.लक्ष्मणन (सुप्रा) और केरल अधिनियम की धारा 3 और 14 में निहित वैधानिक प्रावधान कि रमी मात्र कौशल का खेल है। इस सवाल पर कि क्या रमी एक ऐसा खेल है जिसमें 'कौशल का तत्व' 'मौका का तत्व' से अधिक प्रमुख है और इसे केवल अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है, मेरा मानना है कि धारा 14 ए के तहत अधिसूचना जारी किये बिना भी, रमी मात्र कौशल का खेल बनी हुई है, जैसाकि सत्यनारायण और आर लक्ष्मणन (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस शब्द की व्याख्या की गयी है।

टिप्पणी

इस लेखक का मत है कि जुआ खेलने और जुए में बहुत बड़ा अंतर है। मजे कि बात यह है कि कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक में घुड़दौड़ पर जुए की अनुमति दी है और अन्य गेमिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। वह स्वयं, यह दिया गया है, संवैधानिक रूप से अनुमय है। एक अन्य संभावना मॉडल कानून हो सकती है, जो गेमिंग की अनुमति देता है लेकिन राज्यों द्वारा अपनाने के लिए मॉडल कानून तैयार करके जुआ को सख्ती से नियंत्रित करता है।

सी. क्या केवल प्रासंगिक बने रहने के लिए ब्रॉडबैंड को अपनायेगी?

23 सितंबर 2021 को जारी किये गये 31 जुलाई 2021 के ट्राई के आंकड़ों के अनुसार ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या 808 मिलियन थी। जिसमें से 784.59 मिलियन 455 ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किये गये वायरलेस ब्रॉडबैंड के ग्राहक थे। शेष 24.01 मिलियन वायरलाइन ब्रॉडबैंड ग्राहक थे।

वायरलेस ब्रॉडबैंड - शीर्ष 5 नेटवर्क (वायरलेस ब्रॉडबैंड की कुल बाजार हिस्सेदारी का 98.77%)

- ◆ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (446.68 मिलियन)
- ◆ भारती एयरटेल (201.77 मिलियन)
- ◆ वोडाफोन आइडिया (123.97 मिलियन)
- ◆ वीएसएनएल (24.26 मिलियन) और
- ◆ अटरिया कर्नजंस (01.93 मिलियन)

Wired Broadband - Top 5 Networks (65% of total market share of Wired Broadband)

- ◆ BSNL (05.83 million). -Telecom
- ◆ Bharti Airtel (03.54 million).Telecom
- ◆ Reliance Jio Infocomm Ltd (03.47 million)Telecom
- ◆ Atria Convergence Technologies (01.93 million) Telecom/ Digital TV Services
- ◆ Hathway Cable & Datacom (01.07 million) Multisystem Operator.

1. **Cable Operators** were offered an **Internet Service Provider licence** for the first time in **1999**. This was in terms of **National Telecom Policy 1999**, which gave Cable Broadband priority status for mass deployment of broadband. The policy said that:

- ❖ *Under the Cable Regulation Act, 1995, Cable Service Providers (CSP) shall continue to be freely allowed to provide 'last mile' linkages and switched services within their service areas of operation and run media services, which are essentially one-way, entertainment -related services. Direct interconnectivity between CSP's and any other type of service provider in their area of operation and sharing of infrastructure with any other kind of service provider shall be allowed.*
- ❖ *Interconnectivity between service providers in different service areas shall be reviewed in consultation with TRAI. The same would be announced by 15 August 1999, as a part of the structure for opening up national long distance.*
- ❖ *In view of convergence, it is highly likely that two-way communication (including voice, data, and information services) through cable networks would appear in a significant way in future. The offering of these services through the cable network would be tantamount to supplying fixed services.*
- ❖ *So, in case the above two-way communication services are to be provided by CSPs utilising their network, they would also have to obtain an FSP licence and be bound by the licence conditions of the FSPs, to ensure a level playing field.*

2. Successive **National Telecom Policies** have emphasised the importance of cable broadband. The latest "**National Digital Communications Policy**

वायर्ड ब्रॉडबैंड - शीर्ष 5 नेटवर्क (वायर्ड ब्रॉडबैंड के कुल बाजार हिस्सेदारी का (65%)

- ◆ वीएसएनएल (05.83 मिलियन)-टेलीकॉम
- ◆ भारती एयरटेल (03.54 मिलियन)-टेलीकॉम
- ◆ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (03.47 मिलियन)-टेलीकॉम
- ◆ अटरिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज (01.93 मिलियन)-टेलीकॉम/डिजिटल टीवी सेवायें
- ◆ हैथवे केबल एंड डाटाकॉम (01.07 मिलियन) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

1. **केबल ऑपरेटरों** को **1999** में पहली बार **इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस** की पेशकश की गयी थी। यह **राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999** के संदर्भ में था, जिसने ब्रॉडबैंड की व्यापक तैनाती के लिए केबल ब्रॉडबैंड को प्राथमिकता का दर्जा दिया था। नीति में कहा गया है कि

- ❖ **केबल विनियमन अधिनियम 1995** के तहत, **केबल सेवा प्रदाताओं (सीएसपी)** को संचालन के अपने सेवा क्षेत्रों के भीतर **'अंतिम मील' लिंकेज** और **स्विच** सेवायें प्रदान करने और मीडिया सेवाओं को चलाने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जाती रहेगी, जो अनिवार्य रूप से एकतरफा मनोरंजन संबंधित सेवा है। सीएसपी और उनके संचालन के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदाता के बीच **सीधे इंटरकनेक्टिविटी** और किसी अन्य प्रकार के सेवा प्रदाता के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति होगी।
- ❖ विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी की समीक्षा ट्राई के परामर्श द्वारा की जायेगी। राष्ट्रीय लंबी दूरी को खोलने के लिए संरचना के एक भाग के रूप में **15 अगस्त 1999** तक इसकी घोषणा की जायेगी।
- ❖ **कन्वर्जेंस** को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक संभावना है कि केबल नेटवर्क के माध्यम से **दो तरफा संचार** (वाॉयस, डेटा और सूचना सेवाओं सहित) भविष्य में एक महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देगी। केबल नेटवर्क के माध्यम से इन सेवाओं की पेशकश निश्चित सेवाओं की आपूर्ति के समान होगी।
- ❖ **इसलिए यदि उपरोक्त दोतरफा संचार सेवायें अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए सीएसपी द्वारा प्रदान की जाती हैं तो उन्हें एक एफएसपी लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा और एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एफएसपी की लाइसेंस शर्तों से बाध्य होना होगा।**

2. लगातार **राष्ट्रीय दूरसंचार नीतियों** ने केबल ब्रॉडबैंड के महत्व पर जोर दिया है। नवीनतम **'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति' (एनडीसीपी) 2018** भारत के लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण

(NDCP) 2018 seeks to *unlock the transformative power of digital communications networks to achieve the goal of digital empowerment and well-being of the people of India. There is a need to hasten the implementation of NDCP 2018.*

3. It laid down seven aims by 2022-
 - ❖ Supply **Universal broadband connectivity at 50 Mbps** to every citizen
 - ❖ Supply **1 Gbps connectivity** to all Gram Panchayats of India by **2020** and **10 Gbps by 2022**
 - ❖ Enable **100 Mbps broadband on demand** to all key development institutions, including all educational institutions
 - ❖ Enable **fixed-line broadband access to 50%** of households
 - ❖ Achieve '**unique mobile subscriber density of 55 by 2020 and 65 by 2022.**
 - ❖ Enable **deployment of public Wi-Fi Hotspots;** to reach **5 million by 2020 and 10 million by 2022.**
 - ❖ Ensure connectivity to all uncovered areas.
4. The **Department of Telecommunications** made a series of references to TRAI under **Section 11 (1) (a)** of the **TRAI Act**. Based on these references and after a comprehensive consultation process, **TRAI** issued a very detailed of recommendations titled **Recommendations on Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed** on 31 August 2021, saying that *Reliable and affordable high-speed broadband connectivity are essential to achieve the goal of digital empowerment and improved well-being of the people of India. The Authority has come out with these recommendations to outline a set of policy initiatives needed to boost the penetration of high-speed broadband across the country. A fragmented approach and implementation of selected policy measures in silos will not yield the desired outcome. Hence, it is expected that these recommendations will be accepted by DoT in their entirety to have an overall positive impact on the country's broadband landscape.*
5. This set of **Broadband Recommendations** has a plethora of rarely available data regarding current

और कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने का प्रयास करती है। **एनडीसीपी 2018** के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

3. इसने **2022** तक **सात लक्ष्य** निर्धारित किये हैं:
 - ❖ प्रत्येक नागरिक को **50 एमबीपीएस** पर **यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** की आपूर्ति
 - ❖ **2020** तक भारत की सभी ग्राम पंचायतों को **1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी** और **2022** तक **10 जीबीपीएस** की आपूर्ति।
 - ❖ सभी शैक्षणिक संस्थाओं सहित सभी प्रमुख विकास संस्थानों को **मांग पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड** सक्षम करें
 - ❖ **50%** घरों में **फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड एक्सेस** सक्षम करे।
 - ❖ **2020** तक **55** और **2022** तक **65** तक **अद्वितीय मोबाइल ग्राहक घनत्व** प्राप्त करें।
 - ❖ **सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की तैनाती** सक्षम करें, **2020** तक **5 मिलियन** और **2022** तक **10 मिलियन** तक पहुंच के लिए।
 - ❖ सभी दूरदराज के क्षेत्रों से **संपर्क सुनिश्चित** करें।
4. **दूरसंचार विभाग** ने ट्राई अधिनियम की धारा **11 (1) (ए)** के तहत ट्राई के संदर्भों की एक श्रृंखला बनायी। इन संदर्भों के आधार पर एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद ट्राई ने 31 दिसंबर 2021 को **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और एन्हांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप** पर सिफारिशें शीर्षक से बहुत विस्तृत सिफारिशें जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण और बेहतर कल्याण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वनीय और सस्ती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आवश्यक है। प्राधिकरण इन सिफारिशों के साथ देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों के एक सेट की रूपरेखा तैयार करने के लिए सामने आया है। एक खंडित दृष्टिकोण और साइलो में चयनीत नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन से वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि देश के ब्रॉडबैंड परिदृश्य पर समग्र सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए इन सिफारिशों को दूरसंचार विभाग द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जायेगा।
5. **ब्रॉडबैंड अनुशंसाओं** के इस सेट में वर्तमान ब्रॉडबैंड पैट और

broadband penetration and potential. Salient data is given below:

- ❖ As of **December 2020**, there are approximately **747 million** broadband subscribers in the country. There has been a **33% Compounded Annual Growth Rate (CAGR)** between **2016** and **2020**.

SNAPSHOT OF INDIA'S BROADBAND LANDSCAPE:

- i. As per **Nokia MBiT 2021** report, the overall **average data usage** per month registered a **CAGR of 76%** from **2015** to **2020**, reaching **13.5 GB** in **December 2020**. This could happen due to the continued up-gradation of mobile networks to 4G, which eased increased online education, remote working for professionals and higher OTT viewership.
- ii. There were **724.46 million mobile broadband subscribers** at the end of **December 2020**, which is around **97%** of total broadband connections.
- iii. More than **96%** of these mobile broadband subscribers had **4G connectivity**. As per **Nokia MBiT 2021** report, **4G** constituted **98.7%** of total data traffic consumed across the country.
- iv. India's **digital revolution** continues to be propelled by the rural masses. Rural India will form a sizeable **38%** of broadband users in **2020**. There are **284.64 million** broadband users in rural India. Rural data consumption accounts for around **45%** of overall mobile data usage.
- v. At the end of **December 2020**, there were **22.94 million fixed broadband** connections. *In terms of penetration, it implies that only 9.1 per 100 households have access to fixed broadband.*
- vi. Also, there were only **6.89 million FTTH broadband connections** at the end of December 2020, which is only about 30% of the total fixed broadband connections in the country.
- vii. *Despite the rapid spread of broadband and the increasing agreement on the opportunities it brings, nearly 45% of India's population still does not have broadband access.*
- viii. As far as speed is concerned, as per **Ookla speed test global index March 2021** report, India is experiencing download speeds of **12.15 Mbps** in mobile broadband and around **56.1 Mbps** in case of fixed broadband.
- ix. As per this global index, India ranked **131st** among

क्षमता के संबंध में दुर्लभ रूप से उपलब्ध डेटा की अधिकता है। मुख्य डेटा नीचे दिया जा रहा है:

- ❖ **दिसंबर 2020** तक देश में लगभग **747 मिलियन** ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं। **2016** और **2020** के बीच **33%** चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) रही है।

भारत के ब्रॉडबैंड परिदृश्य का सैपशॉट:

- i. **नोकिया एमबीआईटी 2021** की रिपोर्ट के अनुसार प्रति माह कुल और औसत डेटा का उपयोग ने **2015** से **2020** तक **76%** का **सीएजीआर** दर्ज किया, जो दिसंबर **2020** में **13.5** जीबी तक पहुंच गया। यह मोबाइल नेटवर्क के **4जी** में निरंतर अपडेट के कारण हो सकता है जिससे इसमें आसानी हुई है जिसने ऑनलाइन शिक्षा में वृद्धि, पेशेवरों के लिए दूरस्थ कार्य और उच्च ओटीटी दर्शकों की संख्या को आसान बनाया।
- ii. **दिसंबर 2020** के अंत में **724.46 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहक** थे, जो कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लगभग **97%** है।
- iii. इनमें से **96%** से अधिक मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहकों के पास **4जी कनेक्टिविटी** थी। **नोकिया एमबीआईटी 2021** की रिपोर्ट के अनुसार **4जी** देशभर में खपत किये गये कुल डेटा ट्रैफिक का **98.7%** है।
- iv. भारत की **डिजिटल क्रांति** ग्रामीण जनता द्वारा संचालित की जा रही है। **2020** में ग्रामीण भारत में **38%** ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता होंगे। ग्रामीण भारत में **284.64** मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं। ग्रामीण डेटा खपत कुल मोबाइल डेटा उपयोग का लगभग **45%** है।
- v. **दिसंबर 2020** के अंत में **22.94 मिलियन फिक्सड ब्रॉडबैंड कनेक्शन** थे। *पहुंच के संदर्भ में, इसका तात्पर्य है कि प्रति 100 घरों में केवल 9.1 के पास फिक्सड ब्रॉडबैंड तक पहुंच है।*
- vi. साथ ही **दिसंबर 2020** के अंत में केवल **6.89 मिलियन एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन** थे, जो देश में कुल फिक्सड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लगभग **30%** है।
- vii. ब्रॉडबैंड के तेजी से प्रसार और इसके द्वारा लाये जाने वाले अवसरों पर बढ़ते समझौते के बावजूद, भारत की लगभग **45%** आबादी के पास अभी भी ब्रॉडबैंड की पहुंच नहीं है।
- viii. जहां तक स्पीड का सवाल है तो **ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स मार्च 2021** की रिपोर्ट के अनुसार भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड में **12.15 एमबीपीएस** और फिक्सड ब्रॉडबैंड के मामले में लगभग **56.1 एमबीपीएस** की डाउनलोड स्पीड का अनुभव कर रहा है।
- ix. वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के

140 nations regarding mobile broadband speed and **66th** among **177 countries** in fixed broadband.

6. SUMMARY OF TRAI AUGUST 31, 2020 RECOMMENDATIONS:

6.1. Definition of Broadband

Broadband is a **data connection** that can support interactive services, including Internet access and has the capability of the smallest (lowest) download speed of **2 Mbps** to an individual subscriber from the point of presence (**POP**) of the service provider intending to supply Broadband service. [Para 2.29].

6.2. Broadband Proliferation

To encourage **Cable Operators**, registered under **Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995**, to supply broadband services, issues relating to computation of **Adjusted Gross Revenue (AGR)** for Cable Operators need to be addressed on priority. To address this issue, the Authority has already given its recommendations to the Government dated **6 January 2015**, on "**Definition of Revenue Base (AGR) for the Reckoning of Licence Fee and Spectrum Usage Charges**". [Para 3.39]

❖ The Authority reiterates its earlier recommendation issued in the context of "**Proliferation of Broadband through public Wi-Fi networks**" dated **9 March 2017**, that similar to the **Access Service** authorisation, passive as well as active infrastructure sharing should be allowed under the **Internet Service Licence** and Internet Service authorisation under the **Unified License (U.L.)** and **U.L. (VNO)** licenses. [Para 3.47]

6.3 Broadband Speed Enhancement

- ◆ To ensure efficient utilisation of available spectrum and support mobile broadband speed enhancement, the entire spectrum distributed for **International Mobile Telecommunications (IMT)** purposes should be regularly assigned as per the established procedures. For this purpose, an annual calendar to offer the available **IMT** spectrum for assignment to service providers should be published in advance. [Para 4.23].
- ◆ To enhance the mobile broadband speed in rural and remote areas, using **Bharat Net network**, optical fibre connectivity with **Service Level Agreements (SLA)** should be made available to service providers for

मामले में **140** देशों में **131** वें और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में **177** देशों में **66** वें स्थान पर है।

6. 31 अगस्त 2021 के ट्राई की सिफारिशों का सारांश।

6.1 ब्रॉडबैंड की परिभाषा

ब्रॉडबैंड एक **डेटा कनेक्शन** है जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सेवाओं का समर्थन कर सकता है और ब्रॉडबैंड सेवा की आपूर्ति करने के इच्छुक सेवा प्रदाता की उपस्थिति (पीओपी) से एक व्यक्तिगत ग्राहक को **2एमबीपीएस** की सबसे छोटी (निम्नतम) डाउनलोड गति की क्षमता रखता है। (पैरा 2.29)

6.2 ब्रॉडबैंड का प्रसार

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केबल ऑपरेटरों के लिए **समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)** की गणना से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता पर संबोधित करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए प्राधिकरण ने पहले ही **6 जनवरी 2015** को **सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा पर अपनी सिफारिशें दी हैं। (पैरा 3.39)**

❖ प्राधिकरण ने **9 मार्च 2017** को **सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क** के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार के संदर्भ में जारी अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया कि **एक्सेस सेवा** प्राधिकरण के समान, निष्क्रिय और साथ ही सक्रिय आधारभूत ढांचा के साझाकरण को **इंटरनेट सेवा लाइसेंस** और इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के तहत **एकीकृत लाइसेंस (यूएल)** और **यूएल (वीएनओ)** के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। (पैरा 3.47)

6.3 ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाना

- ❖ उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने और मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति में वृद्धि का समर्थन करने के लिए **अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)** उद्देश्यों के लिए वितरित पूरे स्पेक्ट्रम को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित रूप से सौंपा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सेवा प्रदाताओं को असाइनमेंट के लिए उपलब्ध **आईएमटी** स्पेक्ट्रम की पेशकश करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर अग्रिम रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। (पैरा 4.23)
- ❖ **भारत नेट नेटवर्क** का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं को सेवा स्तर पर समझौतों (**एसएलए**) के

fiberisation of the cellular networks backhaul connectivity. [Para 4.26]

6.4. Right of Way (RoW)

- ◆ As RoW permissions are required by all types of utility service providers, i.e., telegraph, electricity, water, gas, from proper authorities for establishment and maintenance of underground and overground utility infrastructure and presently such permissions are regulated under different Laws, Rules and Regulations, it leads to the cost-inefficient and delayed establishment of utility infrastructure. [Para 5.49].
- ◆ To overcome all these inefficiencies, the Central Government should come out first with the **National RoW Policy**. After, it should also enact a **model law for RoW permissions** which should be adopted by all proper authorities. For this purpose, in coordination with the State Governments, the Central Government should consider the Constitution of a **National RoW Council** so that the policy and legal framework for RoW permissions could be put in place in a time-bound manner. [Para 5.49].
- ◆ Till the time the **National RoW Policy** is notified, the **Governing Council for Broadband**, already setup under the **National Broadband Mission (NBM)**, should lay down *directive principles* for granting **RoW permissions** to all the Central Government Ministries/ Departments so that the **NDCP-2018** aim of efficient establishment of infrastructure is achieved. [Para 5.49]

6.5. National RoW Portal

- ◆ **Sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016** should be amended to include a second provision as:
"Provided further that the Central Government shall establish a single web-based national portal with role-based workflow for RoW permissions."
- ◆ To streamline **Right of Way (RoW)** permission processes and ease establishing a **single-window electronic process (online) for RoW** permission applications, the Central Government should develop a web-based national portal with role-based workflow. It should have clear roles defined for the Central, State, and Local Body authorities. This portal should be developed within one year.

साथ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि सेलुलर नेटवर्क बैकहॉल कनेक्टिविटी के फाइबराइजेशन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। (पैरा 4.26)

6.4 राइट ऑफ वे (आरओडब्लू)

- ◆ चूंकि भूमिगत और भूमिगत उपयोगिता बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव के लिए उचित अधिकारियों से सभी प्रकार के उपयोगिता सेवा प्रदाताओं, यानी टेलीग्राफ, बिजली, पानी, गैस द्वारा **आरओडब्लू** अनुमतियों की आवश्यकता होती है और वर्तमान में ऐसी अनुमतियां विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत विनियमित होती हैं, यह उपयोगिता बुनियादी ढांचे की लागत अक्षम और विलंबित स्थापना की ओर जाता है। (पैरा 5.49)
- ◆ इन सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को पहले **राष्ट्रीय आरओडब्लू नीति** लानी चाहिए। इसके बाद, इसे **आरओडब्लू अनुमतियों के लिए एक मॉडल** कानून भी बनाना चाहिए, जिसे सभी उचित अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय में केंद्र सरकार को एक **राष्ट्रीय आरओडब्लू परिषद** के गठन पर विचार करना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से आरओडब्लू अनुमतियों के लिए नीति और कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। (पैरा 5.49)
- ◆ जबतक **राष्ट्रीय आरओडब्लू नीति** अधिसूचित नहीं हो जाती, तब तक **राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम)** के तहत पहले से स्थापित ब्रॉडबैंड के लिए **गवर्निंग काउंसिल** को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को **आरओडब्लू** अनुमति देने के लिए **निर्देशक सिद्धांत** निर्धारित करने चाहिए ताकि **एनडीसीपी-2018** का लक्ष्य बुनियादी ढांचे की कुशल स्थापना हासिल की है। (पैरा 5.49)

6.5 राष्ट्रीय आरओडब्लू पोर्टल

- ◆ **भारतीय टेलीग्राफ अधिकार नियम 2016 के नियम 4 के उप-नियम (2)** में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इसमें दूसरा प्रावधान शामिल किया जा सके:
‘वशर्ते कि केंद्र सरकार आरओडब्लू अनुमतियों के लिए भूमिका आधारित वर्कफ्लो के साथ एकल वेब आधारित राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करेगी।
- ◆ **राइट ऑफ वे (आरओडब्लू)** अनुमति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और **आरओडब्लू** अनुमति आवेदनों के लिए **सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (ऑनलाइन)** की स्थापना को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार को भूमिका आधारित वर्कफ्लो के साथ एक वेब आधारित राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करना चाहिए। इसमें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं होनी चाहिए। इस पोर्टल को एक वर्ष के भीतर विकसित किया जाना चाहिए।

- ◆ To ease cross-sector collaboration for **RoW** permissions with other utility providers like water, electricity, gas, and co-deployment of telegraph lines with other utility infrastructure creation, at a later date, it should be possible to expand the scope of the proposed national portal to grant **RoW** permissions to other utility providers also.
 - ◆ Wherever Appropriate Authorities, i.e., different Central Government Departments, States, Union Territories, Local Authorities, and their agencies, have already established the web-based portals for grant of **RoW** permissions. The same should be integrated with the proposed national portal for **RoW** permissions.
 - ◆ The proposed national portal for **RoW** permissions should have a facility to give the application in the prescribed format with a dashboard to supply real-time status updates. It should have a provision to make online payments of fees and charges.
 - ◆ It should have the facility to issue electronically signed **RoW** permission, communicate reasons for rejection, if any, to the applicant as per the **Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016**, in advance so that the applicant can give its contentions before rejection of the application.
 - ◆ It should issue a considered permission letter if the proper Authority does not grant or reject the application as specified timelines in the **Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016**.
 - ◆ The proposed national portal for **RoW** permissions should also have the facility to raise a dispute between a licensee and the proper Authority for referring to the dispute resolution officer appointed by the Central Government. [Para 5.59]
- ### 6.6 Laying of Common Ducts
- ◆ The Central Government should incentivise the establishment of common ducts and posts to be shared on a non-discriminatory basis with service providers and infrastructure providers for setting up telegraph and telegraph lines. [Para 5.86]
 - ◆ For planning and development of common ducts and posts infrastructure across the country, a central entity, namely '**Common Ducts and Posts Development Agency (CDPDA)**', on a non-exclusive basis, should be established by the Central Government. [Para 5.100]
- ◆ पानी, बिजली, गैस और अन्य उपयोगिता बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ टेलीग्राफ लाइनों की सह तैनाती जैसे अन्य उपयोगिता प्रदाताओं के साथ **आरओडब्लू** अनुमतियों के लिए क्रॉस सेक्टर सहयोग को आसान बनाने के लिए बाद की तारीख में अन्य उपयोगिता प्रदाताओं को भी **आरओडब्लू** अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल के दायरे का विस्तार करना संभव होना चाहिए।
 - ◆ जहां कहीं भी उपयुक्त प्राधिकरणों, यानी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय प्राधिकरणों और उनकी एजेंसियों ने पहले ही **आरओडब्लू** अनुमतियां प्रदान करने के लिए वेब आधारित पोर्टल स्थापित कर लिए हैं। इसे आरओडब्लू अनुमतियों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
 - ◆ आरओडब्लू अनुमतियों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल में वास्तविक समय की स्थिति अपडेट की आपूर्ति के लिए डैशबोर्ड के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन देने की सुविधा होनी चाहिए। इसमें शुल्क और शुल्क के ऑन लाइन भुगतान करने का प्रावधान होना चाहिए।
 - ◆ इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आरओडब्लू अनुमति जारी करने, **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016** के अनुसार आवेदक को अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, को सूचित करने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि आवेदक आवेदन अस्वीकार होने से पहले अपनी दलीलें दे सके।
 - ◆ यदि उचित प्राधिकारी **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016** में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार नहीं करता है तो उसे एक सुविचारित अनुमति पत्र जारी करना चाहिए।
 - ◆ **आरओडब्लू** अनुमतियों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विवाद समाधान अधिकारी को संदर्भित करने के लिए लाइसेंसधारी और उचित प्राधिकारी के बीच विवाद उठाने की भी सुविधा होनी चाहिए। (पैरा 5.59)
- ### 6.6 सामान्य डक्ट को बिछाना
- ◆ केंद्र सरकार को टेलीग्राफ और टेलीग्राफ लाइनों की स्थापना के लिए सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के साथ गैर भेदभावपूर्ण आधार पर साझा किये जाने वाले सामान्य डक्ट और पोस्ट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (पैरा 5.86)
 - ◆ देशभर में कॉमन डक्ट्स और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और विकास के लिए, केंद्र सरकार द्वारा एक गैर-विशिष्ट आधार पर **कॉमन डक्ट्स एंड पोस्ट्स डेवलपमेंट एजेंसी (सीडीपीडीए)** नामक एक केंद्रीय इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। (पैरा 5, 100)

6.7 Cross-sector infrastructure development

- ◆ As per the design and standards to be finalised by TEC for establishing common ducts infrastructure, a policy should be formulated that mandates co-deployment of common ducts during the construction of any roadway, railway, water pipelines, etc., gas pipelines receiving public funding. Co-deployment of such common ducts could be managed by CDPDA. [Para 5.119]
- ◆ Establishing common ducts for optical fibre cables should be an integral part of Smart City development plans. [Para 5.121]

6.8 Infrastructure Sharing

- ◆ The Authority's earlier recommendations on 'Enhancement of Scope of IP-IRegistration' dated 13 March 2020, should be decided by the DoT, and implemented earliest. The global trend is to move towards *infrastructure sharing*, and this matter needs to be completed within the next 3 months. [Para 5.148].
- ◆ To ease the sharing of passive infrastructure such as ducts, optical fibres, posts. The Authority recommends that:
 - ❖ To ensure common standards for mapping available *passive infrastructure* using the **Geographic Information System (GIS), Telecom Engineering Centre (TEC)** should notify the standards for this purpose.
 - ❖ The *passive infrastructure* available in the country should be mapped by each service provider and infrastructure provider using the **GIS** standardised by **TEC**.
 - ❖ After mapping the *passive infrastructure* details by individual service providers and infrastructure providers, the same should be aggregated on the **common GIS**, which should be kept by the Central Government or the Regulator. The *passive infrastructure* of individual service providers and infrastructure providers available for sharing and selling should be clearly delineated on this system.
- ◆ To ease leasing and trading of *passive infrastructure* efficiently, the Central Government should establish **e-market place(s)** for this purpose. Such an **e-market place** should be able to access the details of the *passive infrastructure* of individual service providers and infrastructure providers, which is delineated for

6.7 क्रॉस-सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

- ◆ सामान्य नलिकाओं के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए **टीईसी** द्वारा अंतिम रूप से दिये जाने वाले डिजाइन और मानकों के अनुसार एक नीति तैयार की जानी चाहिए जो सार्वजनिक धन प्राप्त करने करने वाली किसी भी सड़क, रेलवे, पानी की पाइपलाइन आदि गैस पाइपलाइनों के निर्माण के दौरान आम नलिकाओं के सह तैनाती को अनिवार्य करे। ऐसे सामान्य नलिकाओं की सह तैनाती **सीडीपीडीए** द्वारा प्रबंधित की जा सकती है। (पैरा 5.119)
- ◆ ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए कॉमन डक्ट्स की स्थापना **स्मार्ट सिटी** विकास योजनाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। (पैरा 5.121)

6.8 इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग

- ◆ 13 मार्च 2020 को 'आईपी-पंजीकरण के दायरे में वृद्धि पर प्राधिकरण की पूर्व की सिफारिशों को दूरसंचार विभाग द्वारा तय किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। वैश्विक रुझान बुनियादी ढांचे की हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है और इस मामले को अगले 3 महीने भीतर पूरा करने की जरूरत है। (पैरा 5.148)
- ◆ डक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर, पोस्ट जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के साझाकरण को आसान बनाने के लिए प्राधिकरण अनुसंधान करता है
 - ❖ **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)** का उपयोग करते हुए उपलब्ध निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के मानचित्रण के लिए सामान्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए **दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी)** को इस उद्देश्य के लिए मानकों को अधिसूचित करना चाहिए।
 - ❖ देश में उपलब्ध निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को प्रत्येक सेवा प्रदाता और बुनियादी ढांचा प्रदाता द्वारा **टीईसी** द्वारा मानकीकृत **जीआईएस** का उपयोग करके मैप किया जाना चाहिए।
 - ❖ अलग-अलग सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं द्वारा निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के विवरण को मैप करने के बाद इसे **सामान्य जीआईएस** पर एकत्र किया जाना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार या नियामक द्वारा रखा जाना चाहिए। साझा करने और बेचने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को इस प्रणाली पर स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना चाहिए।
- ◆ निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के पट्टे और व्यापार को प्रभावी ढंग से आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए **ई-मार्केटप्लेस** स्थापित करना चाहिए। इस तरह का **ई-मार्केटप्लेस** व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचे के विवरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, जिसे **सामान्य जीआईएस** प्लेटफॉर्म

sharing and selling on the **common GIS** platform. [Para 5.153]

6.9. Incentives for Proliferation of Fixed Line Broadband [For Cable Operators]

- ◆ *To increase the supply of fixed-line broadband services in rural and remote areas, Cable Operators, who are keen to deliver broadband services, should be encouraged to set up a last-mile linkage network.*
- ◆ *For this purpose, the Government should impart necessary skills to such Cable Operators and supply soft loans to them on easier terms for setting up last-mile connectivity networks in rural and remote areas. As per the extant licensing framework, these Cable Operators could work as franchisees of any ISP, including BBNL, to supply broadband services.*
- ◆ *To incentivise the first investment in the last-mile linkage network and support broadband business operations initially, in the considered view of the Authority, the Government should notify an interest subvention scheme for Cable Operators registered as Micro and Small size enterprises.*
- ◆ *Initially, the proposed incentive, i.e., license fee exemption, to the eligible licensees should be allowed for the smallest period of five years. The need for incentives beyond the first five years may be reviewed in the fifth year keeping in view the policy priorities and technological developments at that point in time. [Para 6.83].*

NOTE 1.

By a Press Note dated 15.09.2021, the **Department of Telecommunications** has given major concessions to the **Telecom Sector**. This is no doubt due to the Vodafone Idea debt default issues. But the new AGR relaxations will help the entire Sector and Cable ISPs.

Key relaxations are:

- ◆ The definition of **AGR** has been rationalised by excluding non-telecom revenue of TSPs, on a **prospective basis**.
- ◆ A moratorium or deferment has been given up to **four (4) years** beginning on **1 October 2021**, in annual payments of dues under S.C.'s judgement; provided, however, the **Net Present Value ("NPV")** of the amounts due still being the same.

पर साझा करने और बेचने के लिए चित्रित किया गया है (पैरा 5.153)

6.9 फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए प्रोत्साहन (केबल ऑपरेटरो के लिए)

- ◆ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरो, जो ब्रॉडबैंड सेवाएँ देने के इच्छुक हैं, को अंतिम मील लिंकेज नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ◆ इस उद्देश्य के लिए सरकार को ऐसे केबल ऑपरेटरो को आवश्यक कौशल प्रदान करना चाहिए और उन्हें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर सॉफ्ट लोन की आपूर्ति करनी चाहिए। मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे के अनुसार ये केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड सेवाओं की आपूर्ति के लिए वीबीएनएल सहित किसी भी आईएसपी के फ्रैंचाइजी के रूप में काम कर सकते हैं।
- ◆ लास्ट माइल लिंकेज नेटवर्क में पहले निवेश को प्रोत्साहित करने और शुरू में ब्रॉडबैंड व्यवसाय संचालन का समर्थन करने के लिए प्राधिकरण के विचार में सरकार को सूक्ष्म और लघु आकार के उद्यमों के रूप में पंजीकृत केबल ऑपरेटरो के लिए एक ब्याज सबवेंशन योजना को अधिसूचित करना चाहिए।
- ◆ प्रारंभ में पात्र लाइसेंसधारियों को प्रस्तावित प्रोत्साहन, यानी लाइसेंस शुल्क में छूट, पांच साल की सबसे छोटी अवधि के लिए दी जानी चाहिए। नीतिगत प्राथमिकताओं और उस समय के तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए पहले पांच वर्षों के बाद प्रोत्साहन की आवश्यकता की समीक्षा पांचवें वर्ष में की जा सकती है। (पैरा 6.83)

नोट 1

दिनांक 15.02.2021 के एक प्रेस नोट द्वारा, **दूरसंचार विभाग** ने **दूरसंचार क्षेत्र** को बड़ी रियायतें दी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ऋण डिफॉल्ट मुद्दों के कारण है। लेकिन नयी एजीआर छूट से पूरे सेक्टर और केबल आईएसपी को मदद मिलेगी।

प्रमुख छूट हैं:

- ◆ **संभावित आधार** पर टीएसपी के गैर दूरसंचार राजस्व को छोड़कर **एजीआर** की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- ◆ एसपी के फैसेल के तहत वकाया के वार्षिक भुगतान में **1 अक्टूबर 2021** से शुरू होने वाले **चार (4) साल** तक की मोहलत दी गयी है, बशर्ते देय राशियों का **शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)** अभी भी वही है।

- ◆ Payments for **spectrum** bought in past auctions (excluding the auction of **2021**) has also been allowed to be deferred for up to **four (4) years** with **NPV** protected at the interest rate stipulated in the respective auctions.
- ◆ TSPs availing of the **moratorium** will have to pay the **Marginal Cost of Funds** based on **Lending Rate + 2% interest (instead of 4%)**. The interest will be compounded *annually* (instead of *monthly*). No penalty or interest on penalty will be payable.
- ◆ At the end of the **moratorium period**, the Government will supply a choice to TSPs to pay the interest amount arising out of the deferment of payment by way of equity and at the choice of the Government to convert their entire dues into equity.

NOTE 2.

By amendments to **Unified Licence** terms dated **23 September 2021** and **25 September 2021**, the Department of Telecom has allowed the sharing of active/passive infrastructure and authorised hub operated by the satellite provider with the satellite bandwidth seeker. This is a significant relaxation given to the Telecom Sector.

COMMENT

The Lockdown, which is ending slowly, has changed traditional T.V. viewing habits. The current number of OTT subscribers is estimated to be between 300 million and 350 million. This is expected to increase over the next few years to between 700 million and 800 million. According to the MX CEO, this surge will lead to huge innovation in content – in formats, genres, and audience segments. It will also mean a much higher consumption of broadband data.

The Nokia MBiT 2021 Report for India estimates only 22 million fixed-line broadband subscribers in India. With over 100 million cable-connected homes, the growth potential is tremendous. FBB revenues as per Nokia will increase at a CAGR of 8.6% during 2020-2025, mainly driven by the adoption of higher value broadband plans, digitalisation and inflated OTT usage, e-learning, and virtual working.

Amid COVID-19, digital services such as e-commerce, online education and entertainment, and e-payments saw a sizeable increase in consumption across the nation. There has been a 30% increase in

- ◆ पिछली नीलामियों (**2021** की नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गये **स्पेक्ट्रम** के भुगतान को भी संबंधित नीलामियों में निर्धारित ब्याज दर पर **एनपीवी** संरक्षित के साथ **चार (4)** वर्षों तक के लिए स्थगित करने की अनुमति दी गयी है।
- ◆ **अधिस्थगन** का लाभ उठाने वाले टीएसपी को **उधार दर + 2% ब्याज (4% के बजाय)** के आधार पर **निधि** की **सीमांत लागत** का भुगतान करना होगा। ब्याज सालाना (मासिक के बजाय) चक्रवृद्धि होगा। जुर्माने पर कोई जुर्माना या ब्याज देय नहीं होगा।
- ◆ **अधिस्थगन अवधि** के अंत में सरकार टीएसपी को इक्विटी के माध्यम से भुगतान के अस्थगन से उत्पन्न ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए और सरकार की पसंद पर उनके पूरे बकाया को इक्विटी में बदलने का विकल्प प्रदान करेगी।

नोट 2

23 सितंबर 2021 और **25 सितंबर 2021** को **एकीकृत लाइसेंस** शर्तों में संशोधन करके, दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट प्रदाता द्वारा संचालित सक्रिय/निष्क्रिय बुनियादी ढांचे और अधिकृत हब को सैटेलाइट बैंडविड्थ साधक के साथ साझा करने की अनुमति दी है। यह टेलीकॉम सेक्टर को दी गयी एक प्रमुख छूट है।

टिप्पणी

धीरे धीरे खत्म हो रहे लॉक डाउन ने पारंपरिक टीवी देखने की आदत में बदलाव आया है। ओटीटी ग्राहकों की वर्तमान संख्या **300** मिलियन से बढ़कर **350** मिलियन के बीच होने का अनुमान है। यह अगले कुछ वर्षों में बढ़कर **700** मिलियन से **800** मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। एमएक्स सीईओ के अनुसार इस उछाल से सामग्री को बहुत फायदा होने वाला है, इसके प्रारूप, शैलियों व दर्शक खंड शामिल हैं। इसका मतलब है कि ब्रॉडबैंड डेटा की बहुत अधिक खपत होगी।

भारत के लिए नोकिया एमबीआईटी **2021** के रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में केवल **22** मिलियन फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं। **100** मिलियन से अधिक केवल से जुड़े घरों के साथ विकास क्षमता जबरदस्त है। नोकिया के अनुसार एफबीवी राजस्व **2020-2025** के दौरान **8.6%** की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो मुख्य रूप से उच्च मूल्य ब्रॉडबैंड योजनाओं को अपनाते, डिजिटलीकरण और बढ़े हुए ओटीटी उपयोग ई-लर्निंग और वर्चुअल वर्किंग से प्रेरित है।

कोविड **19** के बीच ई-कॉमर्स, ऑन लाइन शिक्षा और मनोरंजन जैसी डिजिटल सेवाओं और ई-भुगतान में देश भर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। फरवरी **2020** के बाद शिक्षा ऐप पर खर्च किये गये समय में

time spent on education apps and a 265% increase in April 2020 OTT traffic since February 2020.

Nokia forecasts that the most attractive applications expected to skyrocket data usage include video surveillance, video capture and detection applications, immersive applications experience (AR/VR), smart home, factory, and public safety.

As of 31.03.2021, as per TRAI annual report dated 15.09.2021, there were 907 approved private satellite channels. As of July 31, 2021, the latest TRAI data shows that the total number of active DTH subscribers declined to 69.98 million at the end of March 2021 from 70.99 million at the end of December 2020. This is in addition to the subscribers of D.D. Free Dish (DTH service of Doordarshan).

As per the Media Partners Asia report released on September 16, 2021, Pay-TV subscription revenue is expected to reach \$7.6 billion by 2026 over \$6.4 billion in 2021, in its latest report on India's online video market, highlights "the increasing market share of Direct-to-home (DTH) even as cable T.V. still is in structural decline. There are 127 million pay subscribers, with DTH gaining ground from 2019, reaching 47 per cent, with cable further declining to 53%."

The obvious answer to arrest decline in the Cable Industry is to supply and adopt broadband to the majority of the 100 million cable homes. This would enable the Cable Industry to survive the onslaught of internet content for the next five years.

A key concern has been the AGR concerns and infrastructure sharing concerns which should dissipate after AGR amendments announced by the Government on 15 September and sharing of active and passive infrastructure notifications of 23 September 2021 and September 25, 2021 issued by DOT.

D. MEDIA BRIEF - (MONITORING RECENT DEVELOPMENTS IN THE MEDIA WORLD WITH LONG TERM IMPACT)

1. INDIA TODAY BECOMES BUSINESS-LIKE

There has been a flurry of appointments of business journalists in the past three months in the **India**

30% की बढ़ोतरी हुई और अप्रैल 2020 में ओटीटी ट्रैफिक में 265% की वृद्धि हुई है।

नोकिया ने भविष्यवाणी की है कि डेटा उपयोग में वृद्धि के लिए अपेक्षित सबसे आकर्षक अनुप्रयोगों में वीडियो निगरानी, वीडियो कैप्चर और डिटेक्शन एप्लिकेशन इमर्सिव एप्लिकेशन अनुभव (एआर/वीआर) स्मार्ट होम, फैक्ट्री और सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है।

31.03.2021 तक ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 15.09.2021 के अनुसार 907 अनुमोदित निजी सैटेलाइट चैनल थे। 31 जुलाई 2021 तक ट्राई के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 के अंत में सक्रिय डीटीएच ग्राहकों की कुल संख्या घटकर 69.98 मिलियन रह गयी, जो दिसंबर 2020 के अंत में 70.99 मिलियन थी। यह डीडी के फ्री डिश (दूरदर्शन की डीटीएच सेवा) ग्राहकों के अतिरिक्त है।

16 सितंबर 2021 को जारी मीडिया पार्टनर्स एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऑनलाइन वीडियो बाजार पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पे-टीवी सब्सक्रिप्शन आय 2026 तक 7.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 में 6.4 बिलियन डॉलर से अधिक है। इसमें डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला गया है, भले ही केवल टीवी अभी भी संरचनात्मक गिरावट में है। 127 मिलियन पे टीवी ग्राहक हैं और 2019 से डीटीएच वृद्ध 47 फीसदी तक पहुंच गयी है, जबकि केवल की पहुंच और भी घटकर 53% हो गया है।

केवल टीवी उद्योग के गिरावट को रोकने का स्पष्ट उत्तर 100 मिलियन घरों में से अधिकांश को ब्रॉडबैंड की आपूर्ति करना और उसे अपनाना है। यह केवल उद्योग को अगले पांच वर्षों तक इंटरनेट सामग्री के हमले से बचाने में सक्षम बनायेगा।

एक प्रमुख चिंता एजीआर चिंताओं और बुनियादी ढांचे के वंटवारे की चिंता रही है, जो 15 सितंबर को सरकार द्वारा घोषित एजीआर संशोधनों और डीओटी द्वारा जारी 23 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 की सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना अधिसूचनाओं को साझा करने के बाद समाप्त होनी चाहिए।

डी. मीडिया संक्षिप्त-(दीर्घकालिन प्रभाव के साथ मीडिया जगत में हाल के घटनाक्रमों की निगरानी)

1. इंडिया टूडे बन गया बिजनेस जैसा

इंडिया टूडे गुप में पिछले तीन महीनों में बिजनेस जर्नलिस्ट की नियुक्तियों की झड़ी लग गयी है, जून 2021 में तत्कालीन सीएनबीसी के वेहद प्रसिद्ध व्यवसायी श्री उदयन मुखर्जी, वैश्विक समाचार संपादक

Today Group. In June 2021, the very well-known business whiz kid of erstwhile CNBC, Mr Udayan Mukherjee, joined the Group as Global Business Editor. In September 2021, it appointed Mr Sourav Majumdar, ex-editor of **Fortune India** as editor of the **Business Today magazine** and former **Bloomberg TV Editor** Mr Siddhartha Zarabi, as the Managing Director of **Business Today T.V.**

The Vice-Chairman of the **India Today Group** stated that *the business arena goes through an irreversible change every once in a while; amid this disruptive flutter, the real journalists and real ideas reshape the World. We are happy to be on the leading edge of this transformational journey with the most credible journalists, an enviable legacy and a truly Omni platform multimedia Business Today Experience.*"

The English Business Channel scene is down to **CNBC (T.V. 18/Ambani)** and **E.T. Now (Bennett Coleman/Jain)** groups. **Bloomberg** never got off the ground and still awaits formal entry (maybe with the **Adani group**). **CNBC** leads **E.T. Now**, but both are more trader oriented.

With a booming economy fuelled by foreign funding and bold economic policies of the Central Government, there is a bright future for Business Channels. However, this writer finds Hindi Business Channels are peppier and somewhat more credible.

Let us see whether **India Today** does launch a full-time **Business Today** Channel.

2. TIMES OF INDIA GOES HINDI

On **August 1, 2021**, the **Times Now Group** launched its Hindi News Channel titled **Times Now Navbharat**, the **Times Now Group** claimed its slogan *Ab Badlega Bharat, Banega Navbharat, the Channel would be championing action-oriented journalism driven by decisive and credible content.*

Engaging in pure hyperbole, the **Times Network** claimed that *the Channel is looking at providing innovative content in an interactive way and would engage in-depth analysis based on solution-oriented discussions.*

The Channel is headed by the combative Ms Navika Kumar and will have seven primetime shows with other leading anchors. In weeks, the **Times Network** claimed that its advertiser base had grown from 10 to 30 brands within **August 2021**.

These are early days yet. But in less than two months, **Times Now Network** has announced the launch of its Hindi Business Channel titled **E.T. Now Swadesh**. It will be headed by veteran business anchor Mr Nikunj

के रूप में समूह में शामिल हुए। **सितंबर 2021** में इसने **फॉच्यून इंडिया** के पूर्व संपादक श्री सौरव मजूमदार को **बिजनेस टूडे पत्रिका** का संपादक और **ब्लूमबर्ग टीवी के पूर्व संपादक** श्री सिद्धार्थ जरावी को **बिजनेस टूडे टीवी** का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।

इंडिया टूडे गुप के उप-प्रधान ने कहा कि **व्यापार के क्षेत्र में हर बार एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, इस विघटनकारी स्पंदन के बीच वास्तविक विचार दुनिया को नया रूप देता है। हम सबसे विश्वनीय पत्रकारों, एक गहरी विरासत और वास्तव में ओमनी प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया बिजनेस टूडे अनुभव के साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा के अग्रणी किनारे पर खड़े हैं।**

इंग्लिश बिजनेस चैनल का दृश्य **सीएनबीसी (टीवी 18/अंबानी)** और **ईटी नाउ (बेनेट कोलमैन/जैन)** समूहों के नीचे है। **ब्लूमबर्ग** कभी मैदान पर उतरा ही नहीं और अभी भी औपचारिक प्रवेश की प्रतिक्षा कर रहा है (शायद **अदानी समूह** के साथ)। **सीएनबीसी, ईटी नाउ** से आगे था, लेकिन अब दोनों अधिक व्यापारी उन्मुख हैं।

विदेशी फंडिंग और केंद्र सरकार की साहसिक आर्थिक नीतियों के कारण फलती फूलती अर्थव्यवस्था के साथ बिजनेस चैनलों के लिए उज्ज्वल भविष्य है। हालांकि इस लेखक को लगता है कि हिंदी बिजनेस चैनल अधिक स्वादिष्ट और कुछ अधिक विश्वनीय हैं।

देखना है कि **इंडिया टूडे** पूर्णकालिक **बिजनेस टूडे** चैनल लॉन्च करता है कि नहीं।

2. हिंदी की ओर गया टाइम्स ऑफ इंडिया

1 अगस्त 2021 को **टाइम्स नाउ गुप** ने **टाइम्स नाउ नवभारत** शीर्षक से अपना हिंदी समाचार चैनल लॉन्च किया।

इसकी शुरुआत **टाइम्स नाउ गुप** ने अपने नारे **अब बदलेगा भारत, बनेगा नवभारत** के स्लॉगन के साथ किया। **चैनल, निर्णायक और विश्वनीय सामग्री द्वारा संचालित कार्रवाई उन्मुख पत्रकारिता का समर्थन करेगा।**

शुद्ध अतिशयोक्ति में संलग्न **टाइम्स नेटवर्क** का दावा है कि **चैनल एक इंटीरेक्टिव तरीके से नवीन सामग्री प्रदान करने पर विचार कर रहा है और समाधान उन्मुख चर्चाओं के आधार पर गहन विश्लेषण करेगा।**

चैनल का नेतृत्व जुझारू सुश्री नवीका कुमार कर रही हैं और इसमें अन्य प्रमुख एंकरों के साथ सात प्राइमटाइम शो होंगे। हफ्तों में, **टाइम्स नेटवर्क** ने दावा किया कि **अगस्त 2021** के भीतर उसका विज्ञापनदाता आधार **10 से 30** ब्रांड तक बढ़ गया।

अभी ये शुरुआती दिन हैं। लेकिन दो महीने से भी कम समय में **टाइम्स नाउ नेटवर्क** ने **ईटी नाउ स्वदेश** नाम से अपना हिंदी बिजनेस चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नेतृत्व अनुभवी

Dalmia who will be its Managing Editor who claimed that *with a unique content offering that is focused on empowering viewers with the knowledge that will enable them to be part of India's growth story, ET NOW Swadesh will sharply differentiate itself from other players in the Hindi Business News category.* **E.T. Now Swadesh is being launched on 04.10.2021.**

A recent explosion in interest in retail stock market trading extends to semi-rural and rural India. As per NSDL data, as of **31.08.2021**, Demat account holders exist in **99.28%** of all pin codes in the country. There are a total of **276** Depository Participants. India investors opened **14.2 million** new Demat accounts in the period **2020-2021**.

These are shrewd marketing moves by India's most dynamic news organisation and one of the biggest in the World. Currently, ratings are suspended, but the success of these channels are assured considering that as per **BARCTV Universe Estimates 2020** released in **April 2021** stated The number of households owning a T.V. Set increased to 210 million homes from **197 million** in **2018** while the Hindi Speaking T.V. market grew by **8 per cent** in **2020**.

3. ADANI ENTERS THE MEDIA BATTLEGROUND

A brief announcement on **19.09.2021** that veteran Hindi journalist Mr Sanjay Pugalia as CEO and Editor in Chief of the **Adani Media Group**, comes at a time when media consolation has picked up speed in India with the successful merger of the **Disney Star Group** and now the projected **Zee-Sony** merger.

The fact that a Hindi newspaper has been appointed CEO indicates that the **Adani Group** will start with a clutch of news channels. With over **900** licenced private satellite channels, **Adani group** can buy out existing channels in Hindi and Regional languages.

Based on pure speculation, the shares of **NDTV** hit **upper circuit limits** that may be acquired by the **Adani Group**. This was denied by the Co-Promoters, Dr Prannoy Roy and his wife, Ms Radhika Roy. The company's net profit on a consolidated basis has gone up by **132 %** in the past year.

One news source claims that with Mr Sanjay Pugalia's former employer, **The Quint**, not able to get permission for **Bloomberg** due to unspecified but clearly political factors, the Group may link up with **Bloomberg TV**. There is no official announcement on this unverified news item. ■

विजनेस एंकर श्री निकुंज डालमिया करेंगे, जो इसके प्रबंध संपादक होंगे जिन्होंने दावा किया कि एक अनूठी सामग्री की पेशकश के साथ जो दर्शकों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जो उन्हें भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनने में सक्षम बनायेगी, **ईटी नाउ स्वदेश** हिंदी विजनेस न्यूज श्रेणी के अन्य खिलाड़ियों से खुद को अलग करेगा। **ईटी नाउ स्वदेश** को **04.10.2021** को लॉन्च किया जा रहा है।

खुदरा शेयर बाजार व्यापार में रुचि में हालिया विस्फोट अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण भारत तक फैला हुआ है। **एनएसडीएल** के आंकड़ों के अनुसार **31.08.2021** तक देश के सभी पिन कोड के **99.28%** में डीमैट खाताधारक मौजूद हैं। कुल **276** डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। भारत के निवेशकों ने **2020-2021** की अवधि में **14.2** मिलियन नये डीमैट खाते खोले।

ये भारत के सबसे गतिशील समाचार संगठन और दुनिया में सबसे बड़े में से एक के द्वारा चालाक मार्केटिंग कदम है। वर्तमान में रेटिंग को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इन चैनलों को सफलता का आश्वासन दिया गया है, यह देखते हुए कि **अप्रैल 2021** में जारी **बीएआरसी टीवी यूनीवर्स एस्टीमेट्स 2020** के अनुसार टीवी सेट रखने वाले परिवारों की संख्या **2018** में **197 मिलियन** से बढ़कर **210 मिलियन** हो गयी है, जबकि हिंदी भाषी टीवी बाजार **2020** में **8 फीसदी** बढ़ा।

3. मीडिया के अखाड़े में अडानी का प्रवेश

19.09.2021 को एक संक्षिप्त घोषणा की गयी कि अनुभवी हिंदी पत्रकार श्री संजय पुगलिया, **अडानी मीडिया समूह** के सीईओ और प्रधान संपादक के रूप में ऐसे समय आये हैं जब **डिज्नी स्टार समूह** के सफल विलय के साथ भारत में मीडिया एकीकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ ली है और अब अगला अनुमानित विलय **सोनी-जी** का होगा।

तथ्य यह है कि एक हिंदी अखबार को सीईओ नियुक्त किया गया है, यह दर्शाता है कि **अडानी समूह** समाचार चैनलों के समूह के साथ शुरुआत करेगा। **900** से अधिक लाइसेंस प्राप्त निजी सैटेलाइट चैनलों के साथ **अडानी समूह** हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूदा चैनलों को खरीद सकता है।

शुद्ध अटकलों के आधार पर **एनटीडीवी** के शेयरों ने **ऊपरी सर्किट की सीमा** को पार कर लिया, जिसे **अडानी समूह** द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। सह-प्रवर्तक डॉ प्रणय रॉय और उनकी पत्नी सुश्री राधिका रॉय ने इसका खंडन किया है। समेकित आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले एक साल में **132%** बढ़ा है।

एक समाचार स्रोत का दावा है कि श्री संजय पुगलिया के पूर्व नियुक्ता **द विवंट**, अर्निटिष्ट लेकिन स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारकों के कारण **ब्लूमबर्ग** के लिए अनुमति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, समूह **ब्लूमबर्ग टीवी** के साथ जुड़ सकता है। इस असत्यापित समाचार आइटम पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। ■